सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 281, नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 फिल्म "फतेह"" का गाना हिटमैन रिलीज हुआ
06 विद्यार्थियों को एकता का पाठ पढ़ाती स्कूली पोशाक
08 जेवर एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र अब होगा औद्योगिक क्षेत्र

दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों की जांच में आ रही परेशानी का आखिर दिया परिवहन आयुक्त ने अजूबा हल

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों की परिवहन आयुक्त के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश के बाद से वाहन मालिक अपने वाहन के जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे है और लगातार इसके समाधान के लिए कभी परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, नेता विपक्ष दिल्ली सरकार, पूर्व मेयर, उपराज्यपाल दिल्ली के साथ सभी आला अधिकारियों से बैठकों के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहे है।

लेकिन परिवहन आयुक्त को जनता और व्यवसायिक वाहन मालिकों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ा।

आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देश पर उपायुक्त (वीआईयू) द्वारा एक अनोखा आदेश जारी किया गया जिसका हिन्दी रूपांतर निम्नलिखित है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, झुलझुली, वाहन निरीक्षण इकाई, नई दिल्ली-110073

सूचना :- वाहन मालिक/चालक ध्यान दें

जिन वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त हो चुका है या अगले 15 दिनों में समाप्त होने वाला है, उनके वाहन मालिक निम्नलिखित विवरण के साथ सुविधा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं:

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
JHULJHULI, VEHICLE INSPECTION UNIT, NEW DELHI-110073

NOTICE

ATTENTION VEHICLE OWNERS/DRIVERS

Vehicles owners of vehicles whose fitness certificate has expired or is going to expire in next 15 days may apply at Facilitation Center with the following details:

1. Vehicle Registration number-
2. Chassis Number (Last six digits)-
3. Registered owner name (as per RC)-
4. Category of vehicle (Light Motor vehicle/Heavy Motor Vehicle)-
5. Fitness expiry date-
6. Phone no.-
7. Email address-

(Note: In case the vehicle is attached with the school, the agreement with the school for plying the bus must be attached).

The details can be sent by post at the following address:

To

Facilitation Center (near entry gate no. 1)
Transport Department
5/9 Under Hill Road,
New Delhi-110054

Ordered by
Dy. Commissioner (VIU)

1. वाहन पंजीकरण संख्या-
2. चेसिस नंबर (अंतिम छह अंक)-
3. पंजीकृत मालिक का नाम (आरसी के अनुसार)-
4. वाहन की श्रेणी (हल्का मोटर वाहन/भारी मोटर वाहन)-
5. फिटनेस समाप्ति तिथि-
6. फोन नंबर-
7. ईमेल पता-

(नोटः यदि वाहन स्कूल से जुड़ा है, तो बस चलाने के लिए स्कूल के साथ किया गया अनुबंध संलग्न होना चाहिए)।

ऊपरलिखित विवरण डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता हैः

सुविधा केंद्र (प्रवेश द्वार संख्या 1 के पास) परिवहन विभाग, 5/9 अंडर हिल रोड, नई दिल्ली-110054

आदेश

उप आयुक्त (वीआईयू)

आदेश इसलिए अजूबा है क्योंकि झूलझूली वाहन जांच शाखा में जितने वाहनों की जांच कर वाहन जांच प्रमाणपत्र करने की क्षमता है उससे कम से कम 200% अधिक वाहनों को प्रतिदिन जांच प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वाहन मालिकों से पूर्व सूचना प्राप्त करने पर कैसे परिवहन विभाग वाहनों को जांच करवा कर जांच प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ?

लेकिन परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देश पर उपायुक्त ने आदेश जारी किया है तो कुछ तो सोचा ही होगा, **अब देखते हैं की क्या सोचकर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी करवाया है।**

इसी के साथ विश्वस्त सूत्रों की मानें तो दिल्ली में सबसे कम गिनती वाली दो श्रेणियों को (ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा) जिनकी कुल संख्या अधिकतम 1500 वाहन है और जिसमें से मात्र प्रतिदिन मात्र 5 से 10 वाहन (सालाना/मंथली एवरेज के अनुसार) जांच प्रमाण पत्र के लिए आते है को दिखावे और वाहन मालिकों की एकता तोड़ने के उद्देश्य से झूलझूली वाहन जांच शाखा से बुराड़ी वाहन जांच शाखा में वापिस वाहन जांच के आदेश जारी हो रहे है।

क्या आप भी चाहते है डीजल / पेट्रोल के वाहनों की कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ?

संजय बाटला

आम आदमी की पहुंच में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार की बड़ी घोषणा से गदगद हुए खरीदार, वजह कर देगी हैरान

अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि बहुत जल्द सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को जनता की पहुंच तक पहुंचाने के लिए कई बड़ी घोषणा करने वाला है. बजट सत्र में ईवी वाहनों को सस्ता करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की थी. अब नया बजट सत्र पेश होने वाला है इसलिए फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर बंपर डिस्काउंट की मांग तेज हो गई है.

आपको याद करवा दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कोबाल्ट, लिथियम और तांबे के 7725 महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी. कस्टम ड्यूटी के हटाने से देश में लिथियम आइन बैटरी का उत्पादन सस्ता हो जाएगा. जिसके बाद ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में 40 से 50 प्रतिशत कीमत सिर्फ बैटरी की होती है।

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक निजी कार्यक्रम में संकेत दिये थे कि बहुत जल्द ईवी वाहनों की कीमतें पेट्रोल डीजल वाहनों की बराबर हो जाएगी. हालांकि कब तक होगी, इसके बारे में उन्होने कुछ नहीं बताया था. सूत्रों का दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है. आपको बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार भी अब ईवी वाहनों पर छूट देने के बारे में सोच रही है.

कार, बाइक और स्कूटर के भी सस्ते होने की उम्मीद बैटरी को बनाने में मुख्य तौर पर दो घटको, लिथियम और कोबाल्ट का उपयोग होता है. कस्टम ड्यूटी के हटने से इनकी कीमतों में काफी कमी आएगी. जिससे लिथियम बैटरी से चलने वाली कार, बाइक और स्कूटर की कीमत में काफी गिरावट आ जाएगी. इसका फायदा देश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लाखों ग्राहकों को मिलेगा और साथ ही प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बैटरी से चलने वाले ड्रोन की भी कीमतों में कमी आएगी. कस्टम ड्यूटी छूट के अलावा मंत्री ने इनमे से दो खनिजों पर मूल कस्टम ड्यूटी में कटौती की भी घोषणा की है.

अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो कुछ महीनों का इंतजार करें जिससे आप को आपके पसंद का इलेक्ट्रिक वाहन काफी कम कीमत पर मिल जाएगा और साथ ही राज्य सरकार और भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी अलग। है ना आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर

दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत: इस इलाके में बन सकता है फ्लाईओवर; 50 हजार से ज्यादा लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। साकेत मैक्स अस्पताल के बाहर पंडित त्रिलोक चंद शर्मा मार्ग पर लगने वाले जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी। पीडब्ल्यूडी सड़क चौड़ी करेगा। इसके साथ ही फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार हो रहा है। अभी अकसर इस रोड पर लंबा जाम लगता है। जानिए ट्रैफिक पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग को काम के लिए क्या-क्या शर्तें रखी हैं।

दिल्ली। साकेत स्थित मैक्स सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के बाहर पंडित त्रिलोक चंद शर्मा मार्ग पर दिनभर जाम से जूझने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसको लेकर यातायात पुलिस ने विभाग को काम के लिए एनओसी भी जारी कर दी है। इसके अलावा यहां पर फ्लाईओवर बनाने की संभावना पर भी काम किया जा रहा है।

एक किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ लगता है जाम

पंडित त्रिलोक चंद शर्मा मार्ग पर मैक्स अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले वाहन चालक प्रतिदिन जाम से जूझते हैं। इस मार्ग की तीन में एक लेन पर वाहनों का भयंकर अतिक्रमण रहता है। अवैध पार्किंग में खड़े होने वाले करीब 80 फीसदी वाहन अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके स्वजन के होते हैं। इससे मार्ग पर करीब एक किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ जाम लगा रहता है।

पैदल चलने के लिए भी नहीं मिलता रास्ता

सुबह और शाम को तो पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। अतिक्रमण की समस्या को दैनिक जागरण ने कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया। अब पीडब्ल्यूडी इस मार्ग का चौड़ीकरण करेगी, ताकि यहां यातायात को सामान्य किया जा सके। यातायात पुलिस ने भी विभाग को एनओसी जारी कर दी है।

पुलिस की इन शर्तों का करना होगा पालन

यातायात पुलिस ने हौज रानी से प्रेस एन्क्लेव अपार्टमेंट तक सड़क को चौड़ा करने की अनुमति दी है। इसके तहत काम शुरू करने से पहले सर्विस रोड और फुटपाथ साफ हो और इन्हें चौड़ा किया जाए।

अरबिंदो मार्ग की तरफ से अतिरिक्त लेन बनाई जाए। नई लेन पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाए।

काम शुरू करने से पहले संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

यातायात प्रबंधन के लिए साइट पर मार्शलों की तैनाती हो।

सभी जगहों पर डायवर्जन चेतावनी व सूचना बोर्ड लगाए जाएं।

कार्य के दौरान चेतावनी देने वाली इलेक्ट्रिक बीकन लाइट के साथ पर्याप्त बैरिकेडिंग हो।

आपात स्थिति में अनुमति वापस ले ली जाएगी। कार्य निर्धारित समय में पूरा न होने पर दोबारा अनुमति लेनी होगी।

फ्लाईओवर बनाने पर विचार कर रहा विभाग

सड़क चौड़ीकरण के अलावा इस मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर भी विभाग स्टडी कर रहा है। इसका काम पीडब्ल्यूडी की फ्लाईओवर बनाने वाली युनिट कर रही है। यह फ्लाईओवर मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से हौजरानी को पार करते हुए रेड लाइट से आगे तक बनाया जाएगा।

50 हजार से अधिक वाहन चालक झेलते है परेशानी

वर्तमान में इस मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले 50 हजार से अधिक वाहन चालक जाम में फंसते हैं। यहां पर एमसीडी की दो पार्किंग में से एक में 125 चार पहिया और 22 दो पहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं।

दूसरी 69 चार पहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इसके बावजूद पार्किंग ठेकेदार सर्विस लेन से लेकर फुटपाथ तक वाहन खड़े कराते हैं। अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो हजार मरीज आते हैं, जबकि अस्पताल में करीब 500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है।

साकेत सर्किल में 80 फीसदी चालान मैक्स अस्पताल के बाहर किए

वहीं, यातायात पुलिस ने साकेत सर्किल में जनवरी से अक्टूबर माह तक कुल 22612 चालान किए हैं। कुल चालान में से करीब 80 फीसदी मैक्स अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों के किए गए।

देश में शहरों को अब मेट्रो से जोड़ना होगा आसान इस मशीन से रेल निर्माण में आई क्रांति

परिवहन विशेष न्यूज

टीबीएम मशीन मेट्रो रेल निर्माण में क्रांति ला रही है। चेन्नई स्थित जर्मन कंपनी हेरेनकनेक्ट ने बौमा कानेक्सपो में उन्नत टीबीएम मॉडल का प्रदर्शन किया। यह मॉडल पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और सुरंग निर्माण में लागत कम करता है। टीबीएम मशीन एक घंटे में दो मेगावाट बिजली खपत करती है और सुरंग बनाने के साथ-साथ सीसी का काम भी करती है।

ग्रेटर नोएडा। देश में बड़े शहरों जिनकी आबादी 40 लाख से अधिक है वहां पर मेट्रो रेल का संचालन किए जाने के प्रस्तावों पर जहां निर्माण कार्य आगे बढ़ गया है। वहीं कई बड़े शहर जिसमें कानपुर, बरेली, लखनऊ में मेट्रो रेल का काम प्रगति पर है।

नई दिल्ली, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में काफी हद तक क्षेत्रों को मेट्रो रेल से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में इस मेट्रो रेल ट्रैक को एलीवेटेड बनाने में जहां कम परेशानी होती है। वहीं भूमिगत सुरंग बनाने या मेट्रो ट्रैक बिछाना काफी कठिन होता है।

हर साल 12 से 13 बनाई जा रही टीबीएम मशीन

इनका निर्माण आसानी से हो इसके लिए टीबीएम मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। जो लगातार विकसित रूप में आ रही है। देश में चेन्नई स्थित जर्मन की कंपनी ने एक मात्र प्लांट लगाया है। जिसमें हर वर्ष 12 से 13 टीबीएम मशीन बनाई जा रही हैं।

बीते सप्ताह ही खत्म हुए बौमा कानेक्सपो में टीबीएम मशीन (tbm machine) के उन्त मॉडल का प्रदर्शन किया गया। यह टीबीएम एक किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक चार महीने में बनाकर तैयार कर देगी।

चेन्नई स्थित संयंत्र में टीबीएम मशीन का निर्माण कर रही जर्मन कंपनी हेरेनकनेक्ट ने बौमा कानेक्सपो में जिस उन्नत माडल का प्रयोग प्रदर्शन किया है। वह मेट्रो रेल ट्रैक व हाईड्रो प्रोजेक्ट के लिए है। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक से संचालित है जिसमें किसी तरह के बाहरी ईंधन जैसे डीजल का प्रयोग नहीं हो रहा है।

इससे न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी वहीं सुरंग या मेट्रो ट्रैक के निर्माण में लागत भी कम आएगी। कंपनी के सीईओ मनोज गर्ग ने बताया कि उनकी कंपनी हर वर्ष 12 से 13 टीबीएम मशीन बना रही है। यह पूरी तरह मांग के आधार पर है। क्योंकि यह काफी महंगी है और बाजार सीमित है।

बाजार में कुछ ही कंपनियां मैदान में

कुछ बड़ी कंपनियां ही देश के अंदर सुरंग निर्माण का काम कर रही हैं। इसके संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ भी दक्ष चाहिए। एक घंटे में टीबीएम मशीन दो मेगावाट की बिजली खपत करती है।

इसको तकनीकी तौर पर आटोमेटिक, सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बनाया गया है। प्लांट में 80 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक की टीबीएम मशीन बनाई जा रही है। इसकी मांग आने वाले दिनों में बढ़ेगी। भविष्य को लेकर हम लगातार मशीन में उन्नत परिवर्तन कर रहे हैं।

सुरंग की ड्रिलिंग, दीवारों की सीसी फिंशिंग एक साथ करती है मशीन

टीबीएम मशीन सुरंग बनाने में जहां ड्रिलिंग कर मिट्टी की खुदाई, सुरंग की दीवारों के दोनो तरफ सीसी करने का काम एक साथ करती चलती है। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है जिसको समय के साथ उन्नत किया जाता रहा है।

ट्रैक बिछाए जाने के साथ ही वायरिंग के लिए यह जगह छोड़कर चलती है और इसमें एक साथ कई तकनीकी टीमें काम करती हैं। सीईओ ने बताया कि निर्माण क्षेत्र में कम समय में गुणवत्ता के साथ पर्वतीय राज्यों में सुरंग बनाने में यह कारगर सिद्ध हो चुकी है।

भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब सामान्य क्यों हो गया?

जैसे ही कामदेव ने अपनी कलायों का प्रभाव फैलाया, उसी समय ऐसा कौतुक घटा, कि समस्त संसार उसके वश में हो गया। जिस समय उस मछली के चिन्न की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षमभर में ही वेदों की मर्यादा मिट गई।

नईदिल्ली। विगत अंक में हमने बडे विस्तार से मंथन किया था, कि कामदेव ने अपनी मृत्यु निश्चित जान कर भी, मात्र लोक कल्याण के लिए देवताओं की सहायता करने की ठानी। वह अपने पूरे प्रभाव के साथ भगवान शंकर की समाधि को भंग करने जा पहुँचा। उसने दूर से देखा, कि भोलेनाथ गहन समाधि में लीन हैं। जिन्हें देखकर किसी का भी मन उनके प्रति सुंदर भावों से भर जाये। लेकिन तब कामदेव ने अपने मन को वश में रखा, और अपनी कलायों का विस्तार आरम्भ किया-

'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।
निज बस कीन्ह सकल संसारा।।
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू।
छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू।।'

जैसे ही कामदेव ने अपनी कलायों का प्रभाव फैलाया, उसी समय ऐसा कौतुक घटा, कि समस्त संसार उसके वश में हो गया। जिस समय उस मछली के चिन्न की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षमभर में ही वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संगम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रुपी पर्वत की कन्द्राओं में जा छिपे। कहने का तात्पर्य कि ज्ञान, वैराग्य, संयमख, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता! अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष-बाण उठाया है? संसार में यह दृष्य आम हो गया, कि जितने भी युवावस्था वाले स्त्री-पुरुष थे, वे सब काम के आधीन हो गए। सबके हृदयों में काम भाव की इच्छा प्रबल हो उठी। लताओं के दर्शन कर जितने भी वृक्षों की डालियाँ थी, वे उनकी ओर झुकने लगीं। नदियाँ उमड़-उमड़ कर सागर की ओर दौड़ीं, और ताल-तलैयाँ भी आपस में कामवश होकर संगम करने लगीं-

'जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी।
को कहि सकइ सचेतन करनी।।
पसु पच्छी नभ जल थल चारी।
भए काम बस समय बिसारी।।'

अर्थात जब जड़ की यह दशा कही गई, तब आप अनुमान लगा लीजिए, कि चेतन जीवों की अवस्था को कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरन वाले सारे पशु-पक्षी अपने संयोग का समय विस्मरण कर काम के वश में हो गए। सब लोक काम में ऐसे अँधे हुए कि वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। चकवा-चकवी कोई रात दिन नहीं देख रहे थे। देव-दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल आदि ये सब तो सदा से ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योगरहित या स्त्री के बिरही हो गए।

ऐसे में सोचिए कि जब इतने महान योगी और महा तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तो पामर मनुष्यों की आखिर बात ही क्या करनी। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रीयों सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं, और पुरुष सारे संसार को स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्राह्मण्ड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कोतुक चलता रहा। किसी के भी हृदय में धैर्य न रहा, कामदेव ने सबके मन हर लिए। केवल वे ही बचे जिनकी रक्षा स्वयं श्रीरघुनाथ जी ने की। कामदेव ने वह सब किया, जो उसे करना चाहिए था। केवल भगवान शंकर ही थे, जिन पर उसने अपने अस्त्र अभी चलाने थे। दो घड़ी तक मानों सब तमाशा चलता रहा। तभी कामदेव भगवान शंकर के समक्ष जा पहुँचा। किंतु उसने जैसे ही भगवान शंकर का दर्शन किया, तो वह डर गया। वह भय से काँपने लगा। जिसका प्रभाव यह हुआ, कि समस्त संसार कामदेव के कामभाव से मुक्त हो गया। तब सारा संसार जैसा था, फिर वैसे का वैसा सरल भाव में हो

गया। सब वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग नशा उतर जाने के पश्चात सुखी होते हैं।

भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब सामान्य क्यों हो गया, और क्या कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने में सफल हो पाता है? जानेंगे अगले अंक में---(क्रमशः)---जय श्रीराम।

बीमारियों से बचाव के लिए 30 की उम्र के बाद जरूर कराएं ये जांच, लंबे समय तक रहेंगे स्वस्थ

अच्छी सेहत पाने और बीमारियों से खुद का बचाव करने के लिए सभी लोगों को कुछ प्रकार की जांच कराते रहना चाहिए। भले ही आप स्वस्थ लेकिन फिर भी 30 की उम्र के बाद से आप हर महीने ये 2 जाचें जरूर करानी चाहिए।

नई दिल्ली। अगर आप गंभीर बीमारियों से खुद का बचाव करना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर के लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान दें। आजकल कम उम्र में ही लोगों में क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। वहीं समय पर बीमारी का पता लगाने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते रहें। वहीं जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उनको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, अच्छी सेहत पाने और बीमारियों से खुद का बचाव करने के लिए सभी लोगों को कुछ प्रकार की जांच कराते रहना चाहिए। भले ही आप स्वस्थ और सेहतमंद हैं, लेकिन फिर भी 30 की उम्र के बाद से आप हर महीने ये 2 जाचें जरूर करानी चाहिए।

नियमित रूप से कराएं जांच

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल और डाइट में गड़बड़ी देखी जा रही है। इस कारण सभी उम्र के लोगों को स्वास्थ्य जोखिम हो गया है। हालिया आंकड़ों की बात की जाए, तो 20 से कम उम्र वाले लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और हाई ब्लड शुगर जैसी बीमारियां हो रही हैं। यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आप इन स्वास्थ्य समस्याओं पर निरंतर ध्यान देकर इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके लिए आप नियमित ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच कराते रहें।

ब्लड शुगर की जांच

बता दें कि ब्लड शुगर की जांच कराते रहना डायबिटीज के लिए सबसे जरूरी है। वहीं जिन लोगों को पहले से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है या इंसुलिन लेते हैं। उनको डॉक्टर नियमित जांच की सलाह दे सकते हैं। आप घर पर ही ग्लूकोज मीटर से ब्लड शुगर के लेवल को चेक कर सकते हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज की समस्या रही है। उन लोगों को 30 की उम्र के बाद से हर महीने ग्लूकोज मीटक से और हर 6 महीने के अंतराल पर HbA1c की जांच करानी चाहिए।

ब्लड प्रेशर की जांच

ब्लड प्रेशर के लेवल पर भी ध्यान देते रहना जरूरी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का लेवल अनियंत्रित होने से आंख, हार्ट और किडनी को खतरा हो सकता है। वहीं जिन लोगों के पेरेंट्स या परिवार में किसी को पहले से हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी समस्या रही है, तो इन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो इसकी रीडिंग को एक-दो दिन के अंतराल पर नोट करते रहें। वहीं अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, तो आपको हर महीने इसकी जांच करवानी चाहिए।

जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो यदि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाए, तो गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिए एक नियमित अंतराल पर हार्ट, शुगर और आंखों की जांच कराते रहना चाहिए। वहीं अगर फैमिली में पहले से किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट संबंधी समस्या रही है, तो आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए।

कितनी भी अच्छी डाइट हो या फिर एक्सरसाइज करने का बाद नहीं कम हो रहा वजन, जानें इसके पीछें के कारण

वजन घटाने के लिए आप सभी क्या-क्या नहीं करते हैं। इसके लिए आप कई डाइट प्लान फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो इसके पीछे ये कारण हो सकते है।

नईदिल्ली। बढ़ता हुआ वजन से परेशान रहते हैं। इसके लिए आप हेल्दी डाइट लेते हैं और समय-समय पर एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपको मनचाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है, तो इसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कैसे वर्कआउट करने के बाद भी वजन कम नहीं होता है।

आखिर क्यों बढ़ रहा है वजन

- रात को आप हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डिनर करते हैं, इसिलए भी आपका वजन बढ़ता है।
- अगर आप अत्यधिक तनाव लेते हैं या फिर चिंता में लगे रहते हैं, तो आपके वेट पर असर पड़ता है।
- रात को देर से खाना खाने से।
- बहुत ज्यादा ही हैवी वर्कआउट करने से मसल्स लॉस होने की बजाय स्ट्रेंथ पाती हैं।
- पीरियड्स के दौरान भी कुछ महिलाओं को वजन बढ़ जाता है।
- यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो वेट गेन होगा।
- ज्यादा नमक और सोडियम वाले फूड्स का सेवन न करें। इससे शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है।

कैसे पता करें कि वेट लॉस हो रहा

- इस बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइसज करने से वजन घट रहा है।
- कपड़ों की साइज में बदलाव या फिर फिटिंग चेंज हो गई है।
- शरीर को ज्यादा फ्रेश और स्ट्रॉग महसूस करता है, जैसे कि वेट ट्रेनिंग करना पहले से आसान बना लें।

अंतर्राष्ट्रीय गंभीर समस्या भ्रष्टाचार को हटाएं - नया भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं

नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में भ्रष्टाचार की शून्य सहिष्णुता,पारदर्शी व्यवस्था तथा नागरिकों की मुख्य सहभागिता की प्रतिबद्धता लक्षित करना ज़रूरी भ्रष्टाचार की शून्य सहिष्णुता लाने प्रशासकीय नज़रिए में पारदर्शी व्यवस्था तथा नागरिकों की मुख्य सहभागिता ज़रूरी - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर राजनीतिक भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश देने के लिए दुनियाँ की न्यायपालिकाएं अब कमर कर चुकी है शायद यही कारण है कि दुनियाँ भर में न्यायपालिकाओं के पर खतरे जा रहे हैं,जिसका सटीक उदाहरण बुधवार दिनांक 18 दिसंबर 2024 को देर शाम फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से स्पष्ट होता है,बता दें फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी एक साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ऑफ कसेशन ने बुधवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया, सजा और दोष अब अंतिम हैं। भारत में कुछ महीनों से नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में झंडे गाड़ रहे भारत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इत्यादि अनेक मिशन को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहे हैं जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। और हो भी क्यों ना क्योंकि यह विज़न हमारे पीएम का ड्रीम विज़न है। हम अक्सर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज़न 2047 का जिक्र सुनते हैं, जो हमारे देश के स्वतंत्रत भारत का 100 वाँ साल होगा और हमारे उपरोक्त सभी विज़न का एक डेडलाइन निर्धारित साल है।हम आज से ही इन योजनाओं में सक्रिय हो गए हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसाहोगा। साथियों इस नए भारत में एक बात को प्राथमिकता देना तात्कालिक अनिवार्य है,वह है भ्रष्टाचार को ज़ीरो सहिष्णुता में लाना! क्योंकि यही वह कड़ी है जो प्राथमिकता से सभी योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों को बाधित कर देती है, साथियों जो विकास की योजनाएं चलती है उसमें एक छोटी टेबल से लेकर अंतिम मुख्य टेबल तक का रोल होता है। एक आम आदमी का काम भी एक छोटी टेबल से लेकर मुख्य टेबल तक होता है। परंतु इस बीच में भ्रष्टाचार का दीमक मलाई को चट कर जाता है जिसका दुष्परिणाम आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है, पूरा बोझ इमानदार टैक्सपेयर पर पड़ता है, हमने बुधवार दिनांक 18 दिसंबर 2024 को देर शाम आई रिपोर्ट में देखे कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स,पर्सनल इनकम टैक्स और एसटीटी शामिल हैं, 19.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है,यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 20.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।1 अप्रैल से 17 दिसंबर, 2024 के बीच कुल 3.39 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं,इसे कायम रखने के लिए इस भ्रष्टाचार रूपी दीमक को प्रशासनिक सख्ती, पारदर्शी व्यवस्था और नागरिकों की मुख्य सहभागिता रूपी दवाई से मिटाने में आसानी होगी। हमारे कुछ टेबल वाले अपवाद साथियों को भी सोचना होगा कि, भ्रष्टाचार के नशीले अहसास में रास्ते गलत पकड़ लिये और इसीलिये भ्रष्टाचार की भीड़ में हमारे साथ गलत साथी, संस्कार, सलाह, सहयोग जुड़ते गये। जब सभी कुछ गलत हो तो भला उसका जोड़, बाकी, गुणा या भाग का फल सही कैसे आएगा? तभी भ्रष्टाचार से एक बेहतर हमें अपने परिवार की दुनिया बनाने के प्रयासों के रास्ते में भारी रुकावट पैदा हो रही है, इसका कारण है खोटी कमाई। इसीलिए हम नए भारत, आत्मनिर्भर, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का भारत बनाने के लिए इस दीमक की बीमारी पर योजना बद्ध तरीके से रणनीतिक रोडमैप बनाकर काम करना होगा ताकि भ्रष्टाचारकी शून्य सहिष्णुता हो सके।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार समाप्त करने पर काम करने की करें तो शासन प्रशासन इस दिशा में अनेक योजनाएं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 30 सालों के बाद संशोधन कर नए प्रावधान शामिल कर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 कर उनमें अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें ऐसी कार्रवाई में व्यक्तिगत और कारपोरेट संस्थानों के लिए भी प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था की गई है। परंतु मेरा मानना है कि उसके बाद भी यह दीमक अपनी खुराक बराबर निकाल ही रहा है। साथियों अब समय आ गया है कि इस दीमक के लीकेजेस ढूंढकर उनकी खुराक बंद करने की व्यवस्था की जाए, जो नए और आत्मनिर्भर भारत की नीव के पहियों में से एक साबित होगी।

साथियों बात अगर हम अब छोटी से बड़ी टेबल वालों की करें तो अब उनकी भी ज़वाबदारी, जिम्मेदारी का सही, सचेत समय आ गया है कि हमारे पीएम की बात, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, के मंत्र को एकदम गंभीरता से लेकर उसको अमल करना शुरू कर देंगे तो टेबल वालों का भी नए और आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, क्योंकि दीमक को वह अपने पास फटकने ही नहीं देंगे तो दीमक की मृत्यु होना निश्चित है,जिससे शून्य सहिष्णुता का मंत्र हम खुद ही पा लेंगे।

साथियों बात अगर हम माननीय केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा अनेकों संबोधनों में भ्रष्टाचारीयों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात करने की करें तो, 20 सितंबर 2024 केंद्रीय गृह मंत्री ने साहिबगंज से पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की इसके सभा को संबोधित किया। प्रदेश में पार्टी की सरकार बनाएं, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, परिवर्तन यात्रा पीएम के महान झारखंड विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने का मकसद लेकर आई है। परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने, माता- बहनों को सुरक्षा देने, युवाओं को रोजगार देने, आदिवासी दलित व पिछड़ों का कल्याण करने के लिए आई है। भ्रष्टाचार के मामले पर कहा इन भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि इसका क्रियान्वयन शीघ्र तात्कालिक किया जाए, जिसकी अभी से सीधे रणनीति बनाकर टॉपअप से बॉटमअप तक व 747 जिलों से 5410 से अधिक तहसीलों तक पैनी नजर रखकर ऐसा जाल बिछाया जाए,कि एक चपरासी भी 10 रुपए की रिश्वत लेने से डरे! जिस तरह से माननीय गृहमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं वह अब धरातल पर तात्कालिक लाना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम इस भ्रष्टाचार रूपी दीमक की करें तो यह केवल भारतीय ही नहीं वैश्विक समस्या भी है इसीलिए ही, अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रतिवर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार विरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस भी मनाया जाता है। पूरे विश्व में एक समृद्ध, मूल्याधारित समाज को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इस दिन सम्मेलन, भाषण, रैलियां, प्रदर्शनियां, नाटक आदि कई गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र और संबंधित सदस्य राज्यों के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की भावना के साथ आयोजित की जाती हैं।

साथियों बात अगर हम केंद्रीय पीएमओ राज्यमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम में संबोधन की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने भी पीएम द्वारा दिए गए उस संबोधन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जिसमें पीएम ने कहा, नया भारत अब भ्रष्टाचार को व्यवस्था के हिस्से के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।मंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था को पारदर्शी, सक्षम और दुरुस्त बनाने के प्रयास तेज गति से चल रहे हैं। नए अधिनयम में रिश्वत लेने के साथ-साथ रिश्वत देने को भी अधिनियम में अपराध माना गया है। साथ ही, ऐसी कार्रवाइयों में व्यक्ति और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए एक प्रभावी रोकथाम की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, नागरिकों की सहभागिता और जवाबदेही लाना वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है और इस बात का संकेत देश में उच्च संस्थानों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल की संस्था को संचालित करने की इसकी निर्णायक पहल से मिलता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सरकार द्वारा पिछले वर्षों के दौरान कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि 26 मई, 2014 को पीएम के रूप में शपथ लेने के शीघ्र बाद, पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन, लोकपाल के पद की स्थापित और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एसीसी (नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति) के निर्णयों समेत सभी सरकारी फैसलों को तत्काल सार्वजनिक करने सहित अनेक सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के दौरान 15 सव से अधिक कानूनों को समाप्त कर विभिन्न नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गंभीर समस्या है भ्रष्टाचार नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में भ्रष्टाचार की शून्य सहिष्णुता लाने प्रशासकीय नज़रिए में पारदर्शिता व्यवस्था तथा नागरिकों की मुख्य सहभागिता ज़रूरी है।

ग्लिसरीन देगा चेहरे पर चांद सा निखार, यहां जानिए इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका

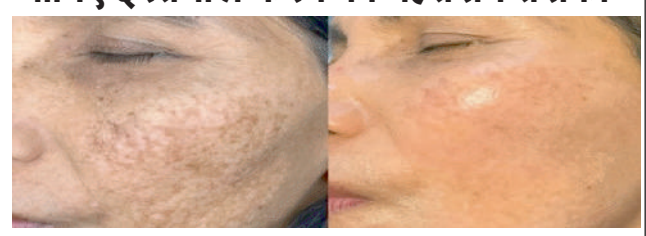

आज हम आपको ग्लिसरीन इस्तेमाल करने के 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फेस से जुड़ी सभी समस्याओं को हर कर देगा। अगर आप ग्लॉसी स्किन पाना चाहते हैं, तो आपको इस इंग्रीडिएंट को अपने स्किन केयर में शामिल करना चाहिए।

नई दिल्ली। हम सभी अपने फेस की हर छोटी समस्या के लिए अलग-अलग ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट की वजह से त्वचा पर रिएक्ट की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं फेस पर एजिंग साइन, एक्ने, डलनेस, फाइन लाइंस और ड्राईनेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ 50 रुपए के एक प्रोडक्ट की सहायता से आप इस सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

दरअसल, आज हम आपको ग्लिसरीन इस्तेमाल करने के 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फेस से जुड़ी सभी समस्याओं को हर कर देगा। अगर आप ग्लॉसी स्किन पाना चाहते हैं, तो आपको इस इंग्रीडिएंट को अपने स्किन केयर में शामिल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप ग्लिसरीन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्किन लाइटनिंग लिक्विड

एलोवेरा जेल- 2 चम्मच
ग्लिसरीन- 1 चम्मच
गुलाब जल- 1 चम्मच

ऐसे तैयार करें फेस लिक्विड

फेस लिक्विड बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच गुलाब जल अच्छे से मिक्स कर लें।

अब इसको फेस पर अप्लाई करते हुए कुछ देर तक मसाज करें।

बता दें कि यह रेमेडी आपके फेस को अलग लेवल पर शाइन देगी। जो आपकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगी।

वहीं अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है। इस नुस्खे को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट लेना न भूलें।

ग्लिसरीन से ब्लीच बनाने का तरीका

ग्लिसरीन- 2 चम्मच
नींबू का रस- 1 चम्मच

ऐसे करें अप्लाई

ग्लिसरीन से ब्लीच बनान के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच गिल्सरीन लें और उसमें 1 चम्मक नींबू का रस मिला लें।

अब फेस को अच्छे से साफकर धो लें।

फिर इसको अपने फेस पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट बार फेस वॉश कर लें।

यह नुस्खा 10 दिन में एक बार आजमाएं।

इससे आपके फेस का निखार कई गुना बढ़ जाता है।

ग्लिसरीन से करें फेस मसाज

आप ग्लिसरीन से फेस मसाज भी कर सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा ग्लिसरीन लें और फेस पर अच्छे से मसाज करें। क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, इसलिए पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। साथ ही आपकी स्किन में मॉइश्चर को भी एड करता है। वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर फेस पर अप्लाई कर सकते हैं।

एक साल की PG डिग्री के लिए हो जाएं तैयार, DU में 2026 से शुरू होगा कोर्स; अपने हिसाब से पाठ्यक्रम का कर सकेंगे चयन

डीयू में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अभी तीसरे सेमेस्टर के बैच की पढ़ाई हो रही है। इसके तहत छात्र पहले साल में पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र को डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। चौथे साल की पढ़ाई करने वाले छात्र को डिग्री के साथ ऑनर्स दिया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप एक साल का परास्नातक 2026 से शुरू हो जाएगा। इसका मसौदा 27 दिसंबर को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि, कुछ शिक्षकों ने इसे जल्दबाजी में चर्चा के लिए लाने का आरोप लगाया है।

डीयू में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अभी तीसरे सेमेस्टर के बैच की पढ़ाई हो रही है। इसके तहत छात्र पहले साल में पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र को डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। चौथे साल की पढ़ाई करने वाले छात्र को डिग्री के साथ ऑनर्स दिया जाएगा।

एक साल में उसे 44 क्रेडिट की डिग्री मिलेगी

छात्र तीसरे साल के बाद दो साल का परास्नातक और चार साल के बाद एक साल का परास्नातक चुन सकते हैं। इसे ही डीयू अब लागू करने जा रहा है। इसके लिए दो साल और एक साल के परास्नातक का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। एक साल के परास्नातक में छात्र को हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट दिए जाएंगे। एक साल में उसे 44 क्रेडिट की डिग्री मिलेगी। जो छात्र दो साल वाले कोर्स में जाएंगे, उन्हें 88 क्रेडिट की डिग्री मिलेगी।

छात्र अपने हिसाब से पाठ्यक्रम का कर सकेंगे चयन

यूजीसी के तय मानकों के अनुसार दो साल वाली डिग्री का लेवल 6.5 और एक साल वाली का सात होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम को कोर्स वर्क, कोर्स वर्क और शोध का संयोजन और सिर्फ शोध इन तीन कैटेगरी में बांटा गया है। प्रवेश के समय छात्र अपने हिसाब से पाठ्यक्रम का चुनाव कर पाएंगे। इसमें शोध के स्तर को अधिक जोड़ा गया है।

एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट को लागू किया जा रहा

डीयू की डीन अकादमिक प्रो. के रत्नाबली ने कहा, ₹पहले हर विभाग ने क्रेडिट अपने हिसाब से तय किए हुए थे। अब इसमें एकरूपता लाने के लिए एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट को लागू किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव उसे बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं।₹ डीयू के मसौदे पर अकादमिक परिषद की सदस्य प्रो. माया जॉन ने कहा, ₹अभी तीसरे साल की पढ़ाई चल रही है और स्नातक के चौथे साल के पाठ्यक्रम को अकादमिक परिषद में चर्चा के लिए नहीं लाया गया है।₹

स्नातक के चौथे साल के पाठ्यक्रम पर होनी चाहिए चर्चा

उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम कई विभागों में तैयार हैं। ऐसे में परास्नातक के पाठ्यक्रम को चर्चा में लाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दो साल के छात्र और एक साल के छात्र पढ़ने से वर्क लोड बढ़ेगा और उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं की गई है। इसलिए पहले स्नातक के चौथे साल के पाठ्यक्रम पर चर्चा की जानी चाहिए।

धक्कामुक्की मामले में राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? भाजपा ने कई धाराओं में दर्ज कराई शिकायत

परिवहन विशेष न्यूज़

संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने दो भाजपा सांसदों को गंभीर चोट पहुंचाई है। इन धाराओं में कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठाई गई है।

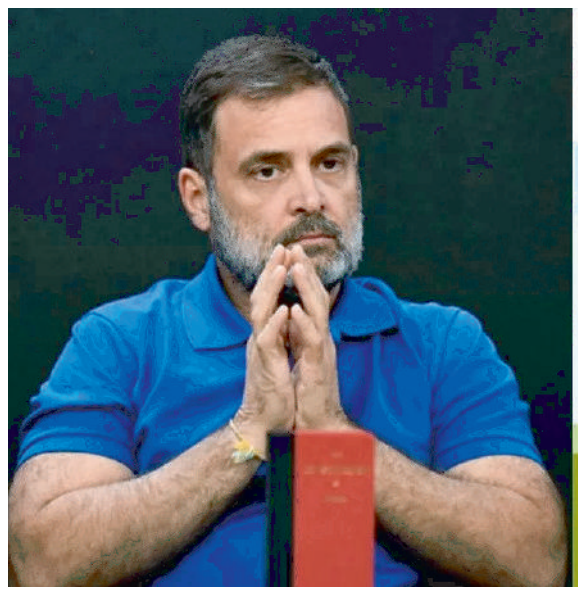

नई दिल्ली। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान बृहस्पतिवार सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित धक्का मुक्की करने के आरोप में भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दी है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा धक्कामुक्की करने से भाजपा के दो सांसदों को गंभीर चोट आई है। इसलिए राहुल व अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, चोट पहुंचाने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का कार्य करने, आपराधिक बल का प्रयोग व आपराधिक धमकी देने आदि धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

सांसद हेमांग जोशी के साथ अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद

संसद भवन के बाहर घटना होने के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर व हेमांग जोशी (Hemang Joshi) ने संसद मार्ग थाने पहुंच कर लिखित शिकायत दी। शिकायत में हेमांग जोशी ने कहा है कि बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे वे साथी सांसद मुकेश राजपूत व प्रताप राव सारंगी समेत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथियों के साथ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

यह विरोध विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सुबह 10.40 वहां पहुंचे। संसद सुरक्षा से निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के अनुरोध के बावजूद राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़े।

FIR में कही गई ये बात

राहुल गांधी और अन्य ने न केवल प्रदर्शनकारी सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने अन्य आईएनडीआई गठबंधन सदस्यों को एनडीए सांसदों पर बल और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाया, जिससे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उन्होंने संसद सदस्य मुकेश राजपूत, प्रताप राव सारंगी और अन्य को धक्का देने के लिए जानबूझकर शारीरिक बल का प्रयोग किया।

सीढ़ियों पर खड़े सांसदों को धक्का देने से कई सांसद गिर गए, उन्हें जानलेवा शारीरिक चोटें लग सकती थी। उक्त घटना प्रताप राव सारंगी के माथे पर चोट लगी। सांसद डॉक्टर बायरेड्डी सबरी जो योग्य चिकित्सक भी हैं, उन्होंने घायल सांसदों को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया। हेमांग जोशी ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस घटना के गवाह हैं क्योंकि वे अपने घायल सहकर्मियों के बगल में खड़े थे और राहुल गांधी और उनके साथियों से बात करने का प्रयास कर रहे थे।

राहुल गांधी की हरकतें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थीं और उन्हें संभावित परिणामों की पूरी जानकारी थी। उन्होंने न केवल आईएनडीआई गठबंधन के अपने साथी सदस्यों को आक्रामक तरीके से काम करने के लिए उकसाया, बल्कि भाजपा सांसदों को शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया।

दिल्ली चुनाव से पहले AAP को तगड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 200 से अधिक कार्यकर्ता; विचारधारा को बताया कारण

परिवहन विशेष न्यूज़

आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने कहा कांग्रेस की विचारधारा व आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व और देशवासियों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले राहुल गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हुए है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. नरेन्द्र नाथ पूर्व विधायक हरि शंकर गुप्ता कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन और विष्णु अग्रवाल शामिल थे।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल, आप के दो सौ से अधिक कार्यकर्ता गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हुए। आप नेता राजकुमार पासवान, रविंद्र सिंह रावत, सुरेंद्र पांचाल विश्वकर्मा, एनआर गुप्ता, आसमां रहमान, हाजी रहास, मोहम्मद मोसिन, अख्तर सिद्दकी, सदाम, काजी हुसैन, केहती प्रसाद ने कांग्रेस की सदस्यता ली।

इन्होंने कहा, ₹कांग्रेस की विचारधारा व आदर्श, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व और देशवासियों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले राहुल गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हुए है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. नरेन्द्र नाथ, पूर्व विधायक हरि शंकर गुप्ता, कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल, जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन और विष्णु अग्रवाल शामिल थे।₹ पार्टी में शामिल हुए नेताओं को कांग्रेस का पटका पहनाया गया।

100 से अधिक नेता कांग्रेस में हुए शामिल

इससे पहले इसी साल अगस्त में बड़े पैमाने पर आप और बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इन्हें शामिल कराया था। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार और पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। इसमें मंगोल पुरी विधानसभा से वार्ड 50 से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद कृष्ण परमाल, वार्ड 51 से पूर्व पार्षद संजय ठाकुर, गौरव शर्मा, बसपा से सुरेंद्र जीतू और दीपक वार्ड 50 से, भाजपा के एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे।

कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की

बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उतारा है। पटपड़गंज सीट से चौधरी अनिल कुमार मैदान में होंगे, जहां से आप के अवध ओझा प्रत्याशी बनाए गए हैं।

देवेंद्र यादव बादली से लड़ेंगे चुनाव

पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से चुनाव मैदान में उतारा है। सीलमपुर से टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल होने वाले अब्दुल रहमान को भी चुनावी रण में उतारा जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ एक बार फिर से बल्लीमारान से चुनाव लड़ेंगे।

दिल्ली में रोज 3000 टन कचरा निस्तारित नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, आतिशी सरकार से मांगा हलफनामा

परिवहन विशेष न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रोजाना करीब 3000 टन कचरे के निस्तारण न हो पाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कचरा प्रबंधन पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली सरकार को हलफनामे में कचरा प्रबंधन नियम 2016 का अनुपालन करते हुए कचरा निस्तारण की टाइमलाइन बतानी होगी। कोर्ट ने कहा है कि रोजाना 3000 टन कचरा अनिस्तारित रहना शर्मनाक है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रोजाना करीब 3000 टन कचरे का निस्तारण न हो पाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कचरा प्रबंधन पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली सरकार को हलफनामे में कचरा प्रबंधन नियम 2016 का अनुपालन करते हुए कचरा निस्तारण की टाइम लाइन बतानी होगी। ये निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को कचरा प्रबंधन और प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिये।

कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में रोजाना करीब 3000 टन कचरा अनिस्तारित रहने को शर्मनाक और चिंतनीय बताते हुए दिल्ली सरकार, एमसीडी और अन्य अथॉरिटीज से इस संबंध में कुछ नया रास्ता निकालने पर विचार करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में रोज निकलने वाले कुल ठोस कचरे और उसके निस्तारण व प्रबंधन पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था, साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में जुड़ने का निर्देश दिया था।

दिल्ली के पास 8073 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित करने की क्षमता

कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कोर्ट में कचरा प्रबंधन पर हलफनामा दाखिल किया था। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि दिल्ली के एमसीडी के क्षेत्र में रोजाना 12 जोन और 250 वार्डों में 11000 टन कचरा निकलता है। दिल्ली के पास 8073 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित करने की क्षमता है जिसमें से 72000 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित किया जाता है जबकि 3800 टन कचरा अनिस्तारित बच जाता है जो कि गाजीपुर और भलस्वा के लैंडफिल क्षेत्र में डाला जाता है।

रोजाना गाजीपुर और भलस्वा में होती है डंपिंग

पीठ ने हलफनामा देखकर मुख्य सचिव से पूछा कि आपकी भविष्य की योजना क्या है। कैसे आप सारे कचरे का प्रबंधन करेंगे क्या आउटर डेड लाइन है। पीठ ने सवाल किया कि 2016 के रूल में टाइम लाइन तय की गई है दिल्ली उसका पालन कैसे कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए कहा है कि 3000 टन कचरा रोजाना अनिस्तारित न करना चौंकानेवाला है। यह शर्म की बात है। रोजाना गाजीपुर और भलस्वा में इसकी डंपिंग की जाती है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह हलफनामे में यह भी बताएगी कि पिछले एक वर्ष में लैंडफिल क्षेत्र में कचरे में कितने बार आग लगी है और इसे रोकने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या उपाय किये गए हैं। कोर्ट ने 15 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में सोनू सूद और यो यो हनी सिंह की फिल्म "फतेह" का गाना हिटमैन रिलीज हुआ

सुषमा रानी

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेता सोनु सूद की आने वाली फिल्म फ़तेह का गाना हिटमैन और टीजर दिल्ली के पीवीआर प्लाजा में में रिलीज हो गया है। इस अवसर पर सोनू सूद अगर यो यो हनी सिंह दोनों मौजूद थे। सोनू सूद की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फतेह का दूसरा ट्रैक हिटमैन जो एक धमाकेदार, डांस एंथम है।यो यो हनी सिंह का गाना हिटमैन लियो ग्रेवाल के बोल और बॉस्को मार्टिस की बेहतरीन कोरियोग्राफी में बनाया गया है। यो यो हनी सिंह के साथ मिलकर काम करने पर सोनू सूद ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा , यह सफ़र तब शुरू हुआ जब हम दोनों पंजाबी सालों पहले चंडीगढ़ में मिले थे। हनी का संगीत उस समय भी सड़कों की धड़कन था और आज भी है।

हिटमैन के लिए उनके साथ काम करना ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने साथ दिया हो। हनी सिंह ने कहा, मैं सोनू सर को 16 साल से भी ज़्यादा समय से जानता हूँ। तब उन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूसर से मेरे लिए बात की मेरे बारे में बताया और मुझे फिल्मों में काम दिलाने की बहुत कोशिश की जब फतेह की बात आई तो मैंने उन्हें एक रफ गाना सुनाया था उन्होंने बोला मैं इसे अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं मैंने बोला नहीं पाजी फतेह के लिए मैं स्पेशल गाना बना कर दूंगा आपको जो मैंने गाना सुनाया था वह फास्ट फूड था मैं आपके लिए स्पेशल पंजाब का सांग बना कर दूंगा हिटमैन मैने सोनू सूद के लिए स्पेशल गाना नहीं पंजाब का सरसों साग बनाया है जो धमाल मचाएगी

, ज़ी स्टूडियोज़ के उमेश केआर बंसल और शक्ति सागर प्रोडक्शंस की सोनाली सूद द्वारा निर्मित और अजय धामा द्वारा सह-निर्मित,फ़िल्म फ़तेह, साइबर अपराध के खिलाफ़ लड़ाई की एक मनोरंजक कहानी है। यह फिल्म 10 जनवरी, 2025 को रिलीज़ होने वाली है।

IC 814: कंधार हाइजैक ने मैचबॉक्स को बड़े सपने देखने और ऊँचा उड़ने के लिए प्रेरित किया

सुषमा रानी

IC 814: कंधार हाइजैक, एक ऐसा ड्रामा जो पाँच हवाई अड्डों, पाँच देशों, सात दिनों, 188 जानों और एक अरब भारतीय दिलों में फैला हुआ था, ने दुनिया भर में दर्शकों का प्यार हासिल किया। यह तीन हफ्तों तक वैश्विक टॉप 10 चार्ट्स में और भारतीय टॉप 10 चार्ट्स में 11 हफ्तों तक बना रहा।

'कहानी कहने की एक मास्टर क्लास,' IC 814: कंधार हाइजैक गूगल पर शीर्ष खोजों में से एक था। सीरीज के बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, 'स्क्रीन पर कैप्टन देवी शरण का किरदार निभाना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। अनुभव सर ने भारतीय सिनेमा के दिग्गजों को इस ऐतिहासिक घटना को फिर से बताने के लिए एकत्र किया। मैं इस मैटचबॉक्स शो को अपने जीवनभर का मान सम्मान मानूंगा.'

मैचबॉक्स शॉट्स के निर्माता संजय राउत्रे ने कहा, 'यह वास्तव में दिल छू लेने वाली बात है कि IC 814: कंधार हाइजैक को वैश्विक दर्शकों से जो प्यार मिला है.'

दिसंबर 2024 भारतीय विमानन इतिहास के सबसे दर्दनाक हाइजैकिंग की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। एक शो जिसे शोध, लेखन और निर्माण में छह साल लगे, IC 814: कंधार हाइजैक कैप्टन देवी शरण और श्रीनजॉय चौधरी की पुस्तक *Flight into Fear: The Captain's Story* का रूपांतरण है।

मैचबॉक्स शॉट्स के तीन साझेदार वैश्विक दर्शकों के साथ गूंजने वाली असाधारण कहानियाँ बताने के अपने संकल्प में एकजुट हैं। वे अपनी परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छे टीमों का निर्माण करते हैं, अपनी टीमों का पूरा समर्थन करते हैं, और मैटचबॉक्स शॉट्स को कहानीकारों के लिए एक आदर्श घर बनाते हैं। इस प्रोडक्शन हाउस के पास कई आशाजनक प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें हंसल मेहता, नवदीप सिंह, जसमीत रीं, सुदीप शर्मा, योगेश चांडेकर और वसन बाला जैसे प्रसिद्ध निर्माता शामिल हैं।

मैचबॉक्स शॉट्स की निर्माता सरिता पाटिल ने कहा, 'वास्तविक जीवन की कहानियाँ, जिन्हें प्रामाणिक रूप से, बारीकी से ध्यान रखते हुए बताया जाता है, दुनिया में गूंजती हैं। यह संभव नहीं होता अगर नेटफ्लिक्स ने मैटचबॉक्स पर विश्वास नहीं किया होता और अनुभव सिन्हा की रचनात्मक नेतृत्व नहीं होती। एक बड़ा धन्यवाद!'

अनुभव सिन्हा, IC 814: कंधार हाइजैक के निदेशक, कहते हैं, 'ऐसी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होतीं; ये हमें असंभव विपत्ति का सामना करते हुए साहस, धैर्य और मानवता की याद दिलाती हैं। इस कहानी को स्क्रीन पर लाना एक विनम्र अनुभव था, और मैं इस प्यार के लिए बेहद आभारी हूं जो इसे दुनिया भर से मिला है।'

29 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ IC 814: कंधार हाइजैक जल्दी ही वैश्विक सनसनी बन गया। इसके रोमांचक कथानक, शक्तिशाली प्रदर्शन और बारीकी से ध्यान दिए गए विवरण के लिए सराहा गया, और शो ने आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त समीक्षा प्राप्त की, जिससे मैचबॉक्स शॉट्स को प्रभावशाली कहानी कहने का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है।

नोएडा पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट बनाने के गंभीर आरोप: समाजसेवी ने कहा, "योगी सरकार से लेकर आयोग तक किसी का डर नहीं"

इशिका मुख्य रिपोर्टर

सार्वजनिक मंच से नोएडा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, क्या कानून के रक्षक खुद कर रहे हैं कानून का उल्लंघन?

नोएडा। पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट बनाने और सत्य को दबाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक प्रमुख समाजसेवी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में माहिर हैं और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार या किसी आयोग का कोई डर नहीं है। यह बयान समाजसेवी ने सार्वजनिक रूप से दिया है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है मामला?

समाजसेवी का कहना है कि नोएडा पुलिस ने कई मामलों में गलत रिपोर्ट तैयार की है और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष नहीं होती और अक्सर प्रभावशाली लोगों के दबाव में की जाती है।

पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप

समाजसेवी ने कहा कि नोएडा पुलिस का रवैया अक्सर राजनीतिक और बाहरी दबाव में होता है। फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भटक रही है और जनता का भरोसा खो रही है। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री और आयोग तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन आरोप लगाया कि पुलिस को किसी का डर नहीं है।

प्रभावशाली लोगों के दबाव में कार्रवाई?

समाजसेवी के मुताबिक, पुलिस ने कई मामलों में प्रभावशाली लोगों के इशारे पर कार्रवाई की है, जिससे आम जनता न्याय से वंचित हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही ढंग से नहीं करता, तो यह जनता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल

यह पहली बार नहीं है जब नोएडा पुलिस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए हैं। फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप ने पुलिस प्रशासन की साख पर बड़ा धक्का पहुंचाया है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

कानूनी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सही हैं, तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस प्रशासन को अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता को साबित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

आगे की राह

समाजसेवी ने इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मानवाधिकार आयोग तक ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी आवाज उठाएं और पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाएं।

नोएडा पुलिस पर लगे ये गंभीर आरोप उनकी कार्यशैली पर गहरा सवाल खड़ा करते हैं। यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह न केवल पुलिस प्रशासन की साख को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि जनता का भरोसा भी पूरी तरह खत्म कर देगा।

ग्रेटर नोएडा: जेल से रिहा हुए और किसान, आंदोलनकारियों को मिल रही राहत

किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में किसानों की रिहाई का सिलसिला जारी, प्रशासन की भूमिका पर नजर -

इशिका मुख्य रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए किसानों को जेल से रिहा किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में कुछ और किसानों को जेल से रिहा किया गया है, जिससे किसानों और उनके परिजनों में राहत की भावना है। इन रिहाइयों को किसान संगठनों की लगातार की गई अपीलों और सरकार के साथ हुए समझौतों का परिणाम माना जा रहा है।

क्या है मामला?

ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में किसान कई वर्षों से अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इन आंदोलनों के दौरान कई किसानों पर कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप लगे और उन्हें जेल भेजा गया।

रिहाई की प्रक्रिया जारी

पिछले कुछ महीनों में प्रशासन ने किसानों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की है। हाल ही में, जेल में बंद कुछ और किसानों को रिहा किया गया है। यह रिहाई किसान संगठनों और सरकार के बीच हुए संवाद और सहमति के बाद हुई है। किसानों के परिजन और ग्रामीण रिहाई के इस कदम से संतोष व्यक्त कर रहे हैं।

किसान संगठनों का बयान

किसान संगठनों ने रिहाई के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह किसानों के संघर्ष की जीत है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सभी किसानों पर लगे केस वापस लिए जाएं और उन्हें पूर्णतः रिहा किया जाए।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

हालांकि, इस रिहाई के साथ प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या किसानों को जेल भेजने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी? और अब रिहाई की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है? किसानों का कहना है कि अगर सरकार पहले ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देती, तो यह स्थिति ही नहीं आती।

आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और प्रशासन को किसानों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। इससे न केवल किसानों का भरोसा जीता जा सकेगा, बल्कि भविष्य में आंदोलन जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा।

किसानों की रिहाई का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि क्या प्रशासन और सरकार इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना सभी संबंधित पक्षों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

महाकुंभ 2025: श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे साइबर अपराधी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

इशिका मुख्य रिपोर्टर

महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। इस धार्मिक उत्सव में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। लेकिन इस आयोजन के नाम पर साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं, जो भोले-भाले श्रद्धालुओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं।

साइबर अपराध का तरीका

पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइट्स, लिंक और कॉल्स के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठग महाकुंभ पास, ऑनलाइन दान, पूजा बुकिंग और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। कई मामलों में श्रद्धालु एडवांस पेमेंट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वेबसाइट या संपर्क नंबर फर्जी था।

फर्जी कॉल्स में ठग श्रद्धालुओं को महाकुंभ में वीआईपी पास या विशेष सुविधाएं देने का दावा करते हैं। इसके अलावा, कुछ ठग QR कोड स्कैन करने के बहाने बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं।

प्रशासन की सतर्कता

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा है कि महाकुंभ से जुड़ी कोई भी जानकारी या सेवा केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल या एजेंसियों के माध्यम से ही ली जाए। फर्जी वेबसाइट्स की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है।

पुलिस की अपील

पुलिस अधिकारियों ने बताया, ₹महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान ठग सक्रिय हो जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि किसी भी संदिग्ध वेबसाइट, लिंक या फोन कॉल से सावधान रहें। अगर आपको किसी प्रकार की ठगी का संदेह हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।"

क्या है समाधान?

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए श्रद्धालुओं को स्वयं सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें किसी भी लिंक पर क्लिक करने या अनजान नंबर पर बैंक डिटेल साझा करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही, प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है।

सवाल उठता है:

महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी आस्था को ठगी से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं या नहीं, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अवसर है, लेकिन साइबर अपराधियों की सक्रियता इसे एक चुनौतीपूर्ण अनुभव बना सकती है। प्रशासन और श्रद्धालुओं को मिलकर इस समस्या से निपटना होगा, ताकि हर कोई सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके।

यमुना सिटी मास्टर प्लान 2041 में बड़ा बदलाव: जेवर एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र अब होगा औद्योगिक क्षेत्र

इशिका मुख्य रिपोर्टर

यमुना सिटी के मास्टर प्लान 2041 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को अब औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन अब अनधिकृत निर्माणों को रोकने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इसे औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है।

नए भू-उपयोग प्रावधान:

इस बदलाव के तहत दो प्रकार के भू-उपयोग प्रावधान किए गए हैं:

1. मल्टीपल लैंड यूज़ इंडस्ट्री:

- 70% क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी।
- 12% क्षेत्र आवासीय होगा।
- 13% क्षेत्र वाणिज्यिक होगा।
- 5% क्षेत्र संस्थागत होगा।

2. मल्टीपल लैंड-हॉस्पिटैलिटी मल्टीपल लैंड यूज़ इंडस्ट्रियलः

- 20% क्षेत्र आवासीय और संस्थागत के लिए होगा।
- 5% क्षेत्र संस्थागत के लिए होगा।

इन प्रावधानों के तहत, उद्योगों को अपने परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

प्रभाव और उद्देश्य:

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही, अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण पाया जाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

आगे की योजना:

यमुना विकास प्राधिकरण (YDA) ने इस बदलाव को मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया है। अब, संबंधित विभागों के साथ मिलकर, इन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि औद्योगिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

यह कदम यमुना सिटी के समग्र विकास और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

"राहुल गांधी के बयान पर बवाल: डॉ. महेश शर्मा ने मांगा इस्तीफा, अंबेडकर के सम्मान की बात उठी"

इशिका मुख्य रिपोर्टर

भारतीय राजनीति में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ये मुद्दे संसद के पटल पर आते हैं और संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में भाजपा सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके संसद में दिए गए बयान पर इस्तीफे की मांग की है।

डॉ. महेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद में डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके योगदान को लेकर ऐसा बयान दिया जो न केवल गलत है बल्कि संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका मानना है कि राहुल गांधी का यह कदम उनके राजनीतिक सोच और जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है। शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले नेता को संसद में बने रहने का अधिकार नहीं है।

क्या है मुद्दा?

राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान कुछ ऐसा कहा जिससे डॉ. अंबेडकर के योगदान को छोटा दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा भाजपा का आरोप है। हालांकि, कांग्रेस इस बयान को अलग तरीके से देख रही है और इसे राजनीतिक साजिश बता रही है।

डॉ. महेश शर्मा का पक्ष

डॉ. महेश शर्मा का कहना है कि डॉ. अंबेडकर केवल संविधान के निर्माता ही नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक न्याय के प्रतीक भी हैं। उनका योगदान हर भारतीय के जीवन में महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी बयान जो उनके प्रति अपमानजनक लगे, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। शर्मा का यह भी कहना है कि राहुल गांधी का यह रवैया दर्शाता है कि वे संसद और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं हैं।

कांग्रेस का पक्ष

कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा की एक सोची-समझी चाल है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके।

सवाल उठता है: क्या इस्तीफा देना सही कदम होगा?

जब कोई बड़ा नेता ऐसा बयान देता है जो विवाद का कारण बनता है, तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि संवेदनशील मुद्दों पर बयान सोच-समझकर दिया जाए।

राहुल गांधी ने डॉ. अंबेडकर के योगदान को लेकर जो भी कहा हो, उसे स्पष्ट करना जरूरी है। अगर बयान गलत है, तो उसे स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए। और अगर आरोप झूठे हैं, तो कांग्रेस को इसे ठोस सबूतों के साथ साबित करना चाहिए।

उच्च पदों पर बैठे नेताओं की जिम्मेदारी

उच्च पदों पर बैठे नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके बयान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश में संदेश पहुंचाते हैं। ऐसे में, उनके शब्दों का चुनाव सोच-समझकर होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि उनका योगदान हर राजनीतिक दल से ऊपर है।

समाज और राजनीति पर प्रभाव

डॉ. अंबेडकर पर विवाद खड़ा करना न केवल उनके सम्मान का अपमान है बल्कि यह समाज में भी गलत संदेश देता है। ऐसे मुद्दे समाज को बांटने का काम करते हैं। राजनीति में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन इसे व्यक्तिगत और असंवेदनशील नहीं बनाना चाहिए।

यह मुद्दा एक संवेदनशील विषय है और इसे राजनीतिक रोटियां सेंकने के बजाय गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, वहीं भाजपा को भी जिम्मेदारी के साथ मुद्दे को उठाना चाहिए। आखिरकार, जनता को उन नेताओं की जरूरत है जो देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए काम करें, न कि विवादों में उलझकर समय व्यर्थ करें।

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता: असमानता और अन्याय को दूर करने की औषधि

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता, जिसे समान नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है, सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक सम्बद्धता कुछ भी हो, व्यक्तिगत मामलों-जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार-को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक ही सेट प्रस्तावित करती है। भारत वर्तमान में हिंदू कानून, मुस्लिम कानून (शरिया) और ईसाई कानून सहित धर्म पर आधारित कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत काम करता है। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का उद्देश्य इन विविध कानूनी प्रणालियों को एक समान संहिता से बदलना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसका लक्ष्य विभिन्न समुदायों में और उनके भीतर कानूनी एकरूपता प्राप्त करना है, जिससे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत में यह प्रावधान है कि ₹राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।₹ हालाँकि, एक निर्देशक सिद्धांत होने के कारण, यह न्यायोचित नहीं है। समान नागरिक संहिता उदार विचारधारा से जुड़ी है और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (भेदभाव का निषेध) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के अंतर्निहित सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

-डॉ.सत्यवान सौरभ

भारत में वर्तमान में पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू नहीं है। इसके बजाय, अलग-अलग समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार अलग-अलग होते हैं। प्रधानमंत्री ने एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत की है, जो डॉ. अंबेडकर के एकीकृत कानूनी ढांचे के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करती है। इस आह्वान का उद्देश्य मौजूदा कानूनों के कथित सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण पहलुओं को सम्बोधित करना और कानूनी प्रणाली को एकीकृत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाले कानूनों को ख़त्म करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। हिंदू कोड बिल सिखों, जैनियों और बौद्धों सहित हिंदुओं के लिए व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध और एकीकृत करने के लिए पेश किया गया। गोवा में गोवा सिविल कोड (पुर्तगाली सिविल कोड 1867) के तहत एक समान नागरिक संहिता है, जो धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना सभी गोवावासियों पर समान रूप से लागू होती है। उत्तराखंड ने हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया है, जो अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करता है।

समान नागरिक संहिता असमानता को बनाए रखने वाले पुराने व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखेगी। यह सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी उपचार सुनिश्चित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक एकीकृत कानूनी ढांचे को बढ़ावा देता है जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों में निहित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगी, विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को। नागरिक कानूनों को मानकीकृत करके, यह सभी के लिए समान अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देगा, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएगा। यहाँ तक कि एक धर्म के भीतर भी, इसके सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक भी सामान्य व्यक्तिगत कानून नहीं है। उदाहरण के लिए, मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण के लिए, कानून जगह-जगह अलग-अलग होते हैं। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों पर केंद्रित है, जिसमें धार्मिक प्रथाओं को अछूता रखा गया है। यह दृष्टिकोण अन्य लोकतंत्रों में प्रथाओं के साथ संरेखित है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के साथ एक समान कानूनी ढांचा मौजूद है। समान नागरिक संहिता भारत के कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाएगी, जटिल और असंगत व्यक्तिगत कानूनों को सरलीकृत प्रणाली से बदल देगी।

इससे कानूनी अनिश्चितता कम होगी और कानूनी खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे व्यक्ति कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में अंतर का फायदा उठा सकते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने से कई व्यक्तिगत कानून विवादों को कुशलतापूर्वक हल करके न्यायपालिका पर बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। इससे अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए संसाधन मुक्त होंगे, जिससे समग्र न्यायिक प्रभावशीलता में सुधार होगा। मार्च 2022 तक भारत की अदालतों में लगभग 4.70 करोड़ मामले लंबित हैं, न्यायपालिका लंबित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष कर रही है। वैश्विक धारणा: समान नागरिक संहिता को अपनाने से समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिल सकता है। संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता धर्म को सामाजिक सम्बंधों और व्यक्तिगत कानूनों से अलग करेगी, समानता सुनिश्चित करेगी और इस प्रकार सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी।

भारतीय कानून पहले से ही कई सिविल मामलों में एक समान संहिता बनाए रखते हैं, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता। हालाँकि, राज्यों ने कई संशोधन किए हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के भीतर भी विविधता आई है। संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) से (आई) और छठी अनुसूची कुछ राज्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है, जो पारिवारिक कानूनों में क्षेत्रीय विविधता की मान्यता को दर्शाती है। समवर्ती सूची में व्यक्तिगत कानूनों को शामिल करना इस विविधता की सुरक्षा का समर्थन करता है, जो अनुच्छेद 44 के तहत एकरूपता के लिए दबाव के साथ विरोधाभास को उजागर करता है। समान नागरिक संहिता भारत के बहुलवादी समाज के लिए ख़तरा हो सकती है, जहाँ लोगों की अपने धार्मिक सिद्धांतों में गहरी आस्था है। भारत के 2018 के विधि आयोग ने कहा कि इस स्तर पर समान नागरिक संहिता ₹न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय₹, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि धर्मनिरपेक्षता को सांस्कृतिक मतभेदों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए, न कि उन्हें कमज़ोर करना चाहिए। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक संयुक्त राष्ट्र के भीतर विविध पहचानों को पहचानने और संरक्षित करने के बारे में है।

समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय पहचान के तहत कई व्यक्तिगत पहचानों के सह-अस्तित्व को संभावित रूप से नष्ट करके इस सिद्धांत के साथ संघर्ष कर सकती है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश या दृष्टिकोण की अनुपस्थिति एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को मिलाने या संवैधानिक जनादेश का पालन करने वाले नए कानून बनाने की जटिलता आम सहमति बनाने को जटिल बनाती है। अल्पसंख्यक अक्सर समान नागरिक संहिता को बहुसंख्यक दृष्टिकोण के थोपे जाने के रूप में देखते हैं, जिससे अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। समान नागरिक संहिता संभावित रूप से एक ऐसी संहिता लागू कर सकती है जो सभी समुदायों में हिंदू प्रथाओं से प्रभावित हो। आदिवासी समुदायों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों में अलग-अलग विवाह और मृत्यु संस्कार होते हैं जो हिंदू रीति-रिवाजों से काफ़ी भिन्न होते हैं। चिंता है कि समान नागरिक संहिता समान प्रथाओं को लागू कर सकती है, जिससे इन अनूठी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना, जहाँ धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

भारत के विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने के बजाय, मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं का अध्ययन और संशोधन करना अधिक विवेकपूर्ण है। समान नागरिक संहिता को भारत की बहुसंस्कृतिवाद को मान्यता देनी चाहिए और इस बात पर बल देना चाहिए कि एकता एकरूपता से अधिक महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा समर्थित है। समान नागरिक संहिता को निष्पक्ष और वैध बनाने के लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श आवश्यक है। सांसदों को समानता और लैंगिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए असंवैधानिक प्रथाओं को हटाने और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता का समर्थन करता है, जिसमें अनुच्छेद 29 (1) विविध संस्कृतियों की सुरक्षा करता है। समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रथाओं को मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समझ और स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

पुराने और विभाजनकारी व्यक्तिगत कानूनों से आगे बढ़ना एक ऐसे भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जहाँ सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जाता है। जैसा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था, ₹कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है, तो दवा दी जानी चाहिए।₹ धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता वह दवा है जिसकी भारत को उस असमानता और अन्याय को दूर करने और ठीक करने की आवश्यकता है जिसने हमारे समाज को लंबे समय से ग्रसित किया है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काइनेटिक ग्रीन ने विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट्स के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कौशल आधारित प्रशिक्षण, शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों में करियर के लिए छात्रों को तैयार करते हुए उद्योग और शिक्षा के बीच संबंध को मजबूत करना है।

समझौते के हिस्से के रूप में, काइनेटिक ग्रीन छात्रों और शिक्षकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और अपनी प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और औद्योगिक स्थलों तक पहुँच प्रदान करेगा। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी अपने पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएगा, छात्रों को पेशेवर अवसरों के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सहयोग में औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप, संकाय विकास पहल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और टिकाऊ ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान प्रयास भी शामिल हैं।

वीआईएंडयू के छात्र काइनेटिक ग्रीन के लिए एआई अवधारणा विकास से संबंधित मार्केटिंग परियोजनाओं और इंटर्नशिप पर भी काम करेंगे, जिससे ऑटोमोटिव क्षेत्र में नवाचार में योगदान मिलेगा।

काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस की संस्थापक और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने उद्योग-अकादमिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'इस साझेदारी का उद्देश्य छात्रों को उद्योग-संबंधित ज्ञान और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जिससे सीखने और नवाचार के अवसर पैदा होंगे।'

वीआईएंडयू के अध्यक्ष भारत अग्रवाल ने साझेदारी के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'यह सहयोग छात्रों और संकाय को उद्योग प्रथाओं से परिचित कराता है और एआई और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत क्षेत्रों में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।'

यामाहा भारत ला रही रेट्रो लुक वाली XSR 155 बाइक, भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में होगी पेश

परिवहन विशेष न्यूज

Yamaha XSR 155 Launch यामाहा भारत में अपनी रेट्रो लुक वाली बाइक को लेकर आने वाली है। इससे पहले वह अपनी इस बाइक को Bharat Mobility Expo 2025 में पेश की जाएगी। यह बाइक कोई और नहीं बल्कि Yamaha XSR 155 है। भारतीय बाजार में यह पेश होने के बाद TVS Ronin से मुकाबला करेगी। आईए जानते हैं कि यह किन खास फीचर्स के साथ आती है।

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जनवरी के 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आयोजित होने वाला है। इसमें कई गाड़ियों पेश होने वाली है। 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में Yamaha XSR 155 भी शोकेस हो सकती है। यह मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल देश में सबसे चर्चित बाइक में से एक है, जिसे यामाहा भारत में लॉन्च करने पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि यामाहा इसे कई कलर ऑप्शन में भारत मोबिलिटी में दिखा सकती है। आइए जानते हैं कि Yamaha XSR 155 किन फीचर्स के साथ आती है।

भारत के लिए क्यों खास

XSR 155 यामाहा इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह MT-15 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे पहले से ही भारत में बनाया जा रहा है। इससे लागत और कीमत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथ ही यामाहा को भारत में मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल को एंट्री कराने में मदद भी मिलेगी।

कैसा है डिजाइन

यामाहा XSR 155 की स्टाइलिंग काफी सिंपल रखी गई है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इसमें आगे की तरफ गोल हेडलाइट से लेकर टियरड्रॉप आकार के फ्यूल टैंक, एक्सपोज़्ड डेल्टा बॉक्स फ्रेम और छोटे फेंडर तक दिया गया है। जिसकी वजह से यह काफी शानदार दिखती है।

इंजन काफी पावरफुल

यामाहा XSR 155 में 155cc, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह बाइक उन लोगों को काफी पसंद आएगी जो रेट्रो लुक की तलाश में रहते हैं। साथ ही इसे युवाओं को भी आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फ्रेम को यूएसडी फोर्क और मोनोशॉक के जरिए सस्पेंड किया गया है। वहीं, इसके आगे और पीछे दोनों पहिए में डिस्क ब्रेक दिया गया है।

Yamaha XSR 155 कीमत

अगर यामाहा की यह बाइक भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश होती है, तो यह संभावित ग्राहकों की रुचि को देखने के लिए एक बेहतरीन मंच होगा और भारतीय बाजार में टीवीएस रोनिन को टक्कर देगी। कंपनी की तरफ से अभी तक इसे भारत में लॉन्च करने की किसी तरह की जानकारी नहीं आई है। अगर यह भारत में लॉन्च होती है तो इसकी कीमत 1.4 लाख रुपये से लेकर 1.8 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

ओला इलेक्ट्रिक की बड़ी योजना, भाविश अग्रवाल 25 दिसंबर को लॉन्च करेंगे 4000 स्टोर, बनेगा रिकॉर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

ओला इलेक्ट्रिक अपनी बिक्री और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25 दिसंबर को रिकॉर्ड 4,000 स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने 'सेविंग वाला स्कूटर' अभियान भी शुरू किया है, जो ईवी को हर भारतीय घर के करीब लाने की कोशिश है। ये स्टोर, जो सर्विस की सुविधा भी देते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को बिक्री और बिक्री के बाद सहायता मिले।

भाविश ने वीडियो में कहा- 'सभी को नमस्कार, मैं भाविश अग्रवाल हूं, मैं ओला इलेक्ट्रिक का संस्थापक हूं। इस साल 25 दिसंबर को हम भारत में ईवी क्रांति को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। आपका पसंदीदा और भारत का नंबर-1 ईवी ब्रांड ओला इलेक्ट्रिक देशभर में 4000 स्टोर लॉन्च करने जा रहा है। हर शहर, हर तहसील, हर तालुका, हर कस्बे, हर जगह एक ओला इलेक्ट्रिक स्टोर और एक ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर होगा। ताकि हर भारतीय अपने भविष्य के लिए ईवी खरीद सके। EV से आप हर महीने 4000 रुपये बचा सकते हैं। इस बचत स्कूटर से आपकी बचत बढ़ेगी, आपका पैसा बचेगा। मैं आप सभी को अपने नजदीकी स्टोर पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ।'

कंपनी ने कहा, 'अपने 'डायरेक्ट टू कंज्यूमर' (D2C) मॉडल का लाभ उठाकर, ओला यह सुनिश्चित कर रही है कि ईवी स्वामित्व हर घर के लिए एक वास्तविकता बन जाए, अपनाने में आने वाली बाधाओं को तोड़कर और बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और दहन ईंधन इंजन वाले वाहनों के स्वामित्व की उच्च लागत से राहत प्रदान करे।' ओला ने हाल ही में गिग और एस1 जेड स्कूटर सीरीज पेश करके अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की जल्द हो सकती है लॉन्चिंग, ईवी सेगमेंट को मिलेगा बूस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार जल्दी ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करने का ऐलान कर सकती है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी और स्टोरेज को लेकर केंद्र सरकार ने इस स्ट्रैटेजिक मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि इस मिशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लांच कर दिया जाएगा। ये मिशन 6 साल की अवधि के लिए शुरू किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत होने से इलेक्ट्रिक व्हेकिल सेगमेंट को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है।

केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए जाने वाले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए प्राथमिक तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंसेंटिव दे सकती है। इसके साथ ही इसमें बैट्री रीसाइकलिंग के लिए भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया जा सकता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ऐलान इसी साल बजट में किया गया था। दावा किया जा रहा है कि इस मिशन में भारत के क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम को चौतरफा समाधान (360 डिग्री सॉल्यूशन) उपलब्ध करने की कोशिश की गई है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत देश में और दूसरे सहयोगी देशों में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और माइनिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इन क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए अलग से इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया जा सकता है। इस मिशन के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में बैट्री रीसाइकलिंग की बात को काफी महत्ता दी गई है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मिनरल्स की रीसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी कोई स्कीम भी लाई जा सकती है।

भारत का ईवी बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का होगा, पांच करोड़ नौकरियों का होगा सृजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार का आकार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है और इससे समूचे ईवी परिवेश में करीब पांच करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। गडकरी ने ई-वाहन उद्योग की स्थिरता पर 8वें 'कैटलिस्ट कांफ्रेंस-ईवी एक्सपो-2024' को संबोधित करते हुए कहा कि अनुमान है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के वित्तपोषण यानी फाइनेंस के बाजार का आकार करीब चार लाख करोड़ रुपये होगा।

हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत में 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है। गडकरी ने कहा कि हम 22 लाख करोड़ रुपये मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं, जो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन का यह आयात हमारे देश में कई समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि भारत की 44 प्रतिशत बिजली की खपत सौर ऊर्जा पर आधारित है।

बायोमास का विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हम जल विद्युत उसके बाद सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा खासकर 'बायोमास' के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सौर ऊर्जा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोतों में से एक है। गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक बसों की समस्या पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा, 'हमारे देश को एक लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है लेकिन अभी हमारे पास केवल 50 हजार बस हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि यही आपके लिए अपने कारखाने का विस्तार करने का सही समय है।' गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से गुणवत्ता के साथ समझौता न करने की बात भी कही।

महंगी हो सकती है सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार

सूत्रों के मुताबिक फिटमेंट कमेटी ने पुरानी छोटी कार व पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर जीएसटी की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। सेकेंड हैंड कार के सप्लायर के मार्जिन पर जीएसटी वसूला जाता है। जीएसटी दर अधिक होने पर सप्लायर सेकेंड हैंड छोटी कार की कीमत बढ़ा देगा। चार मीटर से अधिक लंबाई वाली सेकेंड हैंड कार की बिक्री पर पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

किया सिरोस आज हुई पेश, यहां जानिए बुकिंग और डिलीवरी कब से होगी शुरू

Kia Siros Unveiled Today किआ साइरोस आज भारत में पेश हुई। इसने 6 वेरिएंट में ग्लोबल डेब्यू किया है। इसमें दो इंजन ऑप्शन दिया गया है। सात ही इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) ऑप्शन भी मिलेगा। Kia Syros की कीमतों का खुलासा कंपनी जनवरी 2025 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कर सकती है।

नई दिल्ली। Kia Syros को 19 दिसंबर को भारत में पेश किया गया है। इसे 6 वेरिएंट में लाया गया है, जो HTK, HTK (O), HTK Plus, HTX, HTX Plus और HTX Plus (O) है। कंपनी की तरफ से इसके सभी फीचर्स का खुलासा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कीमतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। कंपनी इसे साल 2025 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं कि Kia Syros की बुकिंग और डिलीवरी कब से शुरू होगी और यह किन फीचर्स के साथ भारत में पेश हुई है।

Kia Syros: दो इंजन ऑप्शन

किआ साइरोस को भारत में दो इंजन ऑप्शन के साथ लाया गया है, जो 1-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन है। इसका 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे मैनुअल ट्रांसमिशन (MT), डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) ऑप्शन के साथ पेश किया गया है।

Kia Syros: इंटीरियर

इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे केबिन थीम दिया गया है। केबिन में 64-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग थीम और डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

इसके साथ ही किआ साइरोस में डुअल 12.3-इंच टचस्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले, 5-इंच की ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन और 8-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, आगे और पीछे की तरफ वेंटिलेटेड सीट और पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

Kia Syros: सेफ्टी फीचर्स

इसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। इसमें किया कनेक्ट 2.0 के साथ कनेक्टिविटी को शामिल करके सुरक्षा को बढ़ाता है। एसओएस आपातकालीन सहायता, रियल टाइम डायगोनोस्टिक और चोरी हुए वाहन की ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इसके साथ ही इसे ADAS लेवल 2 से लैस किया गया है, जिसमें 16 ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स मिलते हैं। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा और स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल है।

Kia Syros: बुकिंग और डिलीवरी

किआ साइरोस को आज पेश किया गया। इस दौरान कंपनी की तरफ से बताया गया कि साइरोस की बुकिंग को 3 जनवरी 2025 से शुरू किया जाएगा। वहीं, इसकी डिलीवरी को फरवरी 2025 से शुरू किया जाएगा। इसकी कीमतों का खुलासा जनवरी 2025 में किया जा सकता है।

विजय गर्ग

अमेरिका में भारतीय छात्र इंजीनियरिंग के बजाय गणित या कंप्यूटर विज्ञान को क्यों पसंद करते हैं?

अमेरिका में भारतीय छात्र इंजीनियरिंग के बजाय गणित या कंप्यूटर विज्ञान को क्यों पसंद करते हैं? विदेशी शिक्षा सलाहकार नौकरी बाज़ार की बदलती माँगों का श्रेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ₹विस्फोटक विकास₹ को देते हैं। 2023-2024 में लगभग 331,602 भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत की वृद्धि है। उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए इंजीनियरिंग अब पहली पसंद नहीं रही। यह नवीनतम ओपन डोर्स रिपोर्ट में सामने आया है, जो अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय गतिविधि की जांच करने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है। जबकि इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय क्षेत्र के रूप में हावी है, हाल के वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में, अमेरिका में लगभग 24.5 प्रतिशत भारतीयों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो 2021-22 में 29.6 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत कम है। इस बीच, गणित या कंप्यूटर विज्ञान भारतीयों को आकर्षित करने वाला सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है, जिसमें 2023-24 में 42.9 प्रतिशत लोग शामिल हैं। गणित और कंप्यूटर विज्ञान इतने लोकप्रिय क्यों हो गए हैं? प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों की तीव्र वृद्धि को देखते हुए, छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित कार्यक्रमों को तेजी से चुन रहे हैं। "यहां तक कि टीओईएफएल (ईटीएस भाषा की क्षमता को मापने के लिए इस मानकीकृत परीक्षण का आयोजन करता है) के अनुसार, अंतर्दृष्टि डेटा, कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी पारंपरिक इंजीनियरिंग प्राथमिकताओं को पार करते हुए, हाल के वर्षों में भारतीय परीक्षार्थियों के बीच लगातार शीर्ष विकल्प रही है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से उच्च रोजगार क्षमता और कैरियर विकल्पों में लचीलेपन जैसे कारकों से प्रेरित है। कंप्यूटर विज्ञान और गणित सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और एनालिटिक्स जैसे उच्च मांग वाले उद्योगों में आकर्षक करियर के लिए मार्ग प्रदान करते हैं ₹ अमेरिका में भारतीय छात्र पिछले वर्ष में भारतीय छात्रों ने गणित/सीएस की जगह गणित/सीएस को प्राथमिकता दी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट एजुकेशन और लाइफलॉन्ग लर्निंग के वाइस डीन डॉ. श्रीदेवी सरमा ने कहा कि इंजीनियरिंग पूरी तरह से लोकप्रियता नहीं खो रही है, यह विकसित हो रही है। "इंजीनियरिंग अब उन क्षेत्रों के साथ बातचीत करती है और वास्तव में उन क्षेत्रों को बदल रही है जिन्हें एक बार 'मात्रात्मक' विश्लेषण और विवरण के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता था। इसमें जीव विज्ञान, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के साथ बातचीत शामिल है... ये सभी डेटा विज्ञान, एआई, मशीन लर्निंग और इसी तरह से बदल रहे हैं।₹ विदेशी शिक्षा सलाहकार भी नौकरी बाजार की इन बदलती मांगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ₹विस्फोटक विकास₹ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सचिन ने कहा, "एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास के साथ, कंप्यूटर विज्ञान बाजार में उन उद्योगों को शामिल करने के लिए काफी विस्तार हो रहा है जहां प्रौद्योगिकी प्रभाव डालने में सक्षम है। इसके अलावा, ये विषय पारंपरिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों के विपरीत, वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक कई क्षेत्रों में करियर के अवसर खोलते हैं, जो अक्सर निश्चित करियर पथ की ओर ले जा सकते हैं।' मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे मुख्य इंजीनियरिंग क्षेत्रों में एआई का एकीकरण आधुनिक इंजीनियरिंग को नया आकार दे रहा है। नौकरी का रुझान वैश्विक बाजार की ओर स्थानांतरित हो गया है, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में। "ये अंतःविषय क्षेत्र अक्सर सिविल, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग जैसे पारंपरिक इंजीनियरिंग विषयों के बजाय गणित और कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। गणित में लचीलापन और प्रयोज्यताऔर कंप्यूटर विज्ञान उद्योगों में व्यापक प्रयोज्यता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में एक मजबूत आधार छात्रों को वित्त और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर तकनीक और परामर्श तक कई प्रकार की भूमिकाओं में आने की अनुमति देता है, जो उन्हें अत्यधिक आकर्षक बनाता है। सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और शिक्षा जैसे अन्य लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में नामांकन आंकड़ों में शायद ही कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में लगभग 11.5 प्रतिशत भारतीय छात्रों ने 2023-24 में प्रबंधन का अध्ययन करना पसंद किया, जबकि 2022-23 में यह 11.6 प्रतिशत और 2021-22 में 13.3 प्रतिशत था। "अधिकांश भारतीय अपनी शिक्षा के निवेश पर रिटर्न का मूल्यांकन करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान पर अधिक जोर देने वाले एसटीईएम क्षेत्रों को अक्सर उच्च-भुगतान वाली, उच्च-मांग वाली नौकरियों के साथ अधिक संरेखित माना जाता है, खासकर सिलिकॉन वैली जैसे तकनीकी केंद्रों में। आधुनिक इंजीनियरिंग समस्याओं में तेजी से कम्प्यूटेशनल सोच और डेटा विश्लेषण शामिल हो रहा है।

परिणामस्वरूप, छात्रों को लग सकता है कि वे कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं, "सरमा ने कहा। अन्य देशों पर अमेरिका क्यों? 2023-2024 में लगभग 3,31,602 भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत की वृद्धि है। भारतीय छात्रों का नामांकन मुख्य रूप से स्नातक स्तर (1,96,567 या 19%) और वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) शैक्षणिक स्तर (97,556 या 41%) पर बढ़ा। फीस निश्चित रूप से कम नहीं है. तो फिर भारतीय छात्रों की पसंद पर अमेरिका का दबदबा क्यों बना हुआ है? जैन के अनुसार, अमेरिका गणित, कंप्यूटर विज्ञान और अन्य एसटीईएम क्षेत्रों सहित विभिन्न विषयों में भारतीय छात्रों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना जारी रखता है, जबकि भारतीय शोधकर्ताओं को आकर्षित करने पर भी जोर दे रहा है। अमेरिका में दुनिया के कुछ शीर्ष विश्वविद्यालय और लचीला पाठ्यक्रम है। उनका एफ-1 वीजा और ओपीटी एसटीईएम स्नातकों को ग्रेजुएशन के बाद तीन साल तक देश में रहने और काम करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें मूल्यवान उद्योग अनुभव हासिल करने और कैरियर के अवसरों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। कई अमेरिकी संस्थान अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है। गणित, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान में उनके स्नातक कार्यक्रम अक्सर वित्त पोषित अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान व्यावहारिक शैक्षणिक और उद्योग अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। ₹अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, जो भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित कर रही है।₹ "दूसरा व्यापक कारण अमेरिकी परिप्रेक्ष्य से है। जब आप दो प्रमुख देशों के बारे में सोचते हैं, तो वे चीन और भारत रहे हैं। मोटे तौर पर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय छात्र आधार का लगभग 60 प्रतिशत इन दो देशों से आता है। जाहिर है, पिछले कुछ वर्षों में, भारत और अमेरिकी सरकारों के बीच बहुत मजबूत संबंध रहे हैं और यह (चीन के साथ) पहले जैसे नहीं रहे हैं। यदि आप चाहें तो वास्तव में यही इस असमानता का कारण है।₹ इंजीनियरों की अधिक आपूर्ति भारतीय छात्रों को अपनी मातृभूमि में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जहां कुछ हजार सीटों के लिए दस लाख से अधिक लोग संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में बैठते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति दर कम है। बैंकों द्वारा छात्र ऋण को प्रोत्साहित करने के साथ, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना भारतीयों के लिए आकर्षक है। "इसके अतिरिक्त, पारंपरिक क्षेत्रों में बीटेक स्नातकों की अधिक आपूर्ति और विशिष्ट डोमेन में विशेष कौशल की बढ़ती मांग इस बदलाव के प्रमुख चालक हैं। अकॉर्डिनग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन (जीआरई) डेटा के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्र उम्मीदवार पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तुलना में भौतिक विज्ञान के लिए स्पष्ट प्राथमिकता दिखा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों (2018-2023) में, जीआरई के माध्यम से इंजीनियरिंग चुनने वाले भारतीय छात्रों का प्रतिशत लगातार 11-13 प्रतिशत के आसपास रहा है, जो एक दशक पहले देखे गए अधिक प्रमुख आंकड़ों से गिरावट को दर्शाता है।" पिछले कुछ वर्षों में, और विशेष रूप से महामारी के बाद, आईआईटी और एनआईटी जैसे अग्रणी भारतीय तकनीकी संस्थान अक्सर प्रसिद्ध के सहयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इलेक्ट्रिक वाहन और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अंतःविषय पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालय. हालाँकि, यहाँ चीज़ें अभी शुरू ही हुई हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी पारंपरिक शाखाएँ मुख्य शाखाओं में नौकरियाँ प्रदान करने में विफल हैं। ससेक्स विश्वविद्यालय (2022-23) में एमएससी डेटा साइंस की पढ़ाई करने वाले क्षितिज पाठक ने कहा कि स्नातक के दौरान उनकी मुख्य शाखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमई) थी, लेकिन भारत या यहां तक कि विदेशों में भी कम विकल्प हैं। "एमई से, आप डेटा साइंस पर स्विच कर सकते हैं। गणित डेटा विज्ञान का मूल है। यदि आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं, तो आप आसानी से एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। वैश्विक बाजार को देखते हुए, गणित या सीएस में अधिक अवसर हैं।" श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (यूएस) के अनुसार, गणित व्यवसायों से संबंधित नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि अंकगणित का उपयोग करने वाले और गणना करने, डेटा का विश्लेषण करने और समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करने वाले पदों में इस दशक के अंत तक प्रति वर्ष 30,000 से अधिक की वृद्धि होगी। मई 2023 में गणितज्ञों का औसत वार्षिक वेतन $116,440 था। तो यह समझ में आता है कि विश्व स्तर पर इंजीनियर पारंपरिक शाखाओं में कम रुचि क्यों ले रहे हैं।

विद्यार्थियों को एकता का पाठ पढ़ाती स्कूली पोशाक

विजय गर्ग

स्कूल शिक्षा का मंदिर है, जहां ज्ञान का प्रसार होता है और बच्चे के सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। इस ज्ञान के विस्तार से बालक में अच्छे गुण प्रकट होते हैं। इन्हीं अच्छे गुणों के कारण बच्चे अपना जीवन सुखी बनाते हैं और उन्नति करते हैं। हर संगठन के कुछ नियम होते हैं, जिसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को उसके प्रबंधन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के नियमों का पालन करेंभी अनिवार्य रूप से करना होगा. उनमें से एक है स्कूल यूनिफॉर्म, जिसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को पहनना जरूरी होता है, जो हर संस्थान की एक अलग पहचान बनाता है। स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब है वो विशेष कपड़े जो छात्र स्कूल में पहनते हैं। स्कूल की वर्दी स्कूल के नियमों के अनुसार डिज़ाइन की गई है। यह वर्दी छात्रों की पहचान, विद्यालय की विशिष्टता, एकता और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करती है। वर्दी में अक्सर स्कूल का लोगो और रंग शामिल होते हैं। इसे पहनकर बच्चा खुद को उस स्कूल का छात्र मानता है, जहां उसे पढ़ाई के लिए जाना है। विशिष्ट पहचान हर स्कूल की अलग-अलग यूनिफॉर्म होती है, जिससे स्कूल की पहचान बनती है। हर स्कूल में यूनिफॉर्म का एक ही रंग होता है. इसे पहनकर बच्चे एक जैसे दिखते हैं। यूनिफॉर्म के साथ-साथ जब बच्चे टाई-बेल्ट और आई कार्ड पहनते हैं तो इससे स्कूल की पहचान का स्तर और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा, जब छात्र असेंबली में इकट्ठा होते हैं तो वे अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्कूल के बाहर के लोगों के बीच अपने संस्थान की अधिक पहचान बनाता है। पहली आम पहचान है स्कूल यूनिफॉर्मछात्रों को एकता की श्रृंखला में ले जाता है। वे किसी भी प्रकार के आर्थिक या सामाजिक भेदभाव से मुक्त रहते हैं। किसी भी छात्र को महंगे या रंग-बिरंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं होता। वे खुद को एक संगठन का हिस्सा मानते हैं और एक दोस्ताना माहौल बनाते हैं। पढ़ाई में आसानी एक बहुत ही आरामदायक स्कूल वर्दी. विद्यार्थी पढ़ते समय सहजता महसूस करते हैं। सभी की वेशभूषा एक जैसी होने से उनका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकता। इससे छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता हैसमस्याओं से जूझने की कोई जरूरत नहीं है. भेदभाव दूर होता है प्राचीन काल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का चलन नहीं था। बच्चे मनचाहे रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल आते थे। इससे बच्चे ऊंच-नीच का शिकार होते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया है। अब हर स्कूल की अलग-अलग यूनिफॉर्म होती है, जिसे पहनना बेहद अनिवार्य है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से छात्रों में समानता और एकता की भावना आती है। विद्यार्थी चाहे अमीर घर का हो या गरीब घर का, एक ही वर्दी उन्हें सभी मतभेदों से दूर रखती है। अनुशासनहर संस्थान का अपना एक अनुशासन होता है, जिसका पालन करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वर्दी पहनने से वे स्कूल के अनुशासन का पालन करते हैं और पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाते हैं। वे न केवल अपने शिक्षकों की बात ध्यान से सुनते हैं बल्कि उनकी हर बात मानते भी हैं, जिससे उनका विकास होता है। इस प्रकार स्कूल की वर्दी छात्रों में कड़ी मेहनत, अनुशासन और सामाजिक सावधानी के गुण पैदा करती है। विद्यार्थियों में सहयोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थियों में आपसी सहयोग और मित्रता की भावना बढ़ती हैहै वे समझते हैं कि हम सब एक जैसे हैं और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है।' ऐसी मानसिकता छात्रों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। इससे उन्हें घनिष्ठ मित्रता और अच्छे सहपाठियों का एहसास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक और दिलचस्प बनाता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं उत्साह पैदा होता है। माता-पिता के लिए कम लागत स्कूल यूनिफॉर्म का चयन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिससे इसे खरीदना आसान रहता है। सब कुछ एक ही जगह से सस्ते में मुहैया कराया जाएगाहै, जिससे अनावश्यक परेशानी का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। बच्चे स्कूल जाने के लिए ज्यादा रंग-बिरंगे कपड़े

खरीदने की जिद न करें क्योंकि स्कूल के लिए हर रोज यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। उनका ध्यान सिर्फ वर्दी पर ही केंद्रित रहता है. इसका फायदा यह होता है कि अभिभावकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। दूसरे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह अच्छी बात है कि सरकार ने मुफ्त यूनिफॉर्म की सुविधा दी है. इसका सारा खर्च शासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है, जो सराहनीय है। बच्चों परअगर अभिभावक चाहें तो अपनी सुविधा के लिए और भी यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है.

जिज्ञासा की यात्रा

विजय गर्ग

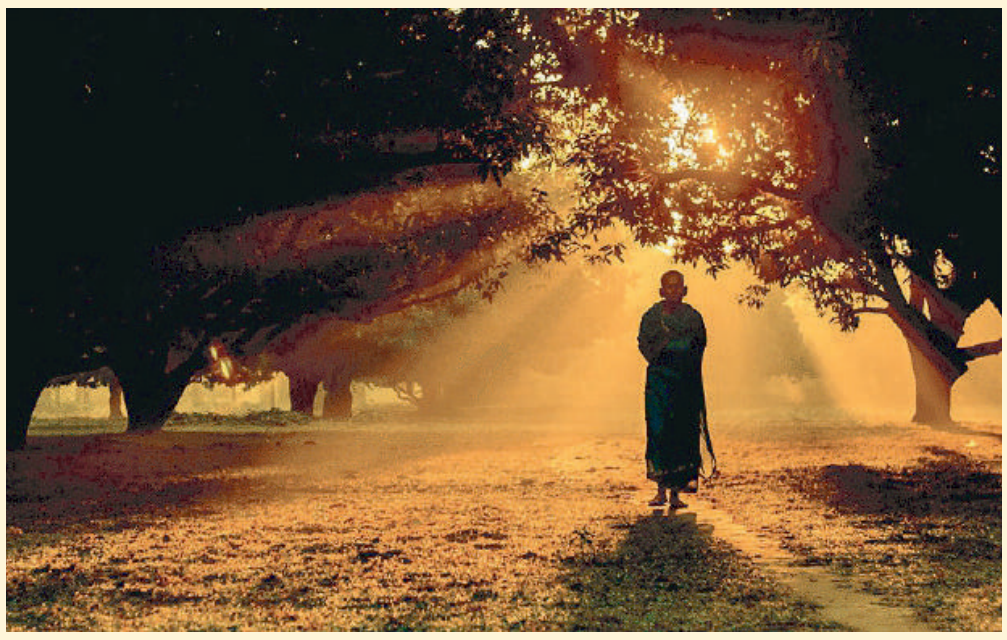

मनुष्य के मस्तिष्क में कई प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म लेकर पूरे जीवन काल तक सक्रिय रहती हैं। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के शांत मन में सकारात्मक सोच या कल्पना की ग्रंथि अधिक तीव्र होती है। किसी विषय के बारे में जानने या समझने की मानसिक स्थिति को हम सामान्य रूप में जिज्ञासा मानते हैं। दुनिया में जिस भी विषय पर चिंतन, सिद्धांत, आविष्कार आदि निरूपित किए गए, वे सभी जिज्ञासा की कोख की ही देन कही जा सकती है। व्यक्ति की किसी संदर्भ को गहराई से जानने की आतुरता जिज्ञासा में परिणत हो जाती है । संसार के लेखक, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में जब जिज्ञासा की तरंगों ने अपनी पहचान बनाई होगी, तभी समाज को विभिन्न कोटि के लेख, साहित्य, कविता, दर्शनशास्त्र, वैज्ञानिक आविष्कार आदि ने मूर्त रूप लिया होगा। एक प्रकार से कल्पना के प्रस्थान बिंदु को जिज्ञासा का उदगम स्थल कहा जा सकता है।

जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति सदैव अपनी सक्रियता बोध के सहारे कुछ न कुछ जानने-सीखने की विधा में क्रियाशील रहते हैं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अध्ययन कक्ष में हमेशा विद्वानों का जमघट लगा रहता था जो प्लेटो से सदैव कुछ नया विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते थे। यह विचित्र है कि प्लेटो कभी अपने को ज्ञानी नहीं समझते थे और वे खुद सदा कुछ नया सोचने-विचारने में व्यस्त रहते थे। कभी-कभी तो वे छोटे बच्चों और युवकों से भी कुछ सीखने के लिए उनमें घुल-मिल जाते थे । प्लेटो की इस आदत पर उनके एक परम मित्र ने उनसे प्रश्न किया कि 'आप इतने विख्यात दार्शनिक हैं, विश्व के प्रतिष्ठित तर्कशास्त्रियों में आपकी गणना होती है, फिर भी आप किसी भी बड़े या छोटे से गुण ग्रहण करने और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक क्यों रहते हैं। आप तो दूसरों का स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, फिर आपको सीखने या जानने की भला क्या जरूरत है। कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए तो उनसे सीखने का दिखावा नहीं करते।' अपने मित्र के भोलेपन पर प्लेटो हंसे फिर उन्होंने कहा- 'मेरे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसे उत्तम गुण हैं जो अन्य के पास नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे से सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति दूसरों से सीखने-समझने में झिझक या संकोच करेगा तब तक वह बहुत से अच्छे ज्ञान से वंचित ही रहेगा ।'

विचारणीय है कि जिज्ञासा की उत्पति का स्रोत क्या है। कई चिंतकों का मानना है कि यह प्रवृत्ति ज्ञानकोश से उत्पन्न होती है । जैसा कि विदित हैं कि मनुष्य के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसे मानव शरीर का तृतीय नेत्र भी कहा गया है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर जब उन्मुख करता है तो उसमें कल्पना और जिज्ञासा जैसी प्रवृत्ति मूल रूप से प्रभावित करती है। यों कहें कि हमारी उत्कट जिज्ञासा ही ज्ञान का दर्पण तैयार करती है । जिज्ञासा सीखने की सतत प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण जन्मजात प्रवृत्तियों में से यह एक मुख्य है, जिसमें उम्र सीमा बाधक नहीं बनती है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि जिज्ञासा व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव के मनोभावों का वह समूह या उत्सुकता की वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य किसी वस्तु या घटना को, जो उसके लिए अप्रत्यक्ष हो, जानने के लिए बेसब्र रहता है।

किसी छविगृह में कोई प्रेरक चलचित्र के प्रदर्शन के बाद उसकी सकारात्मक चर्चा समाज में जब होने लगती है तो सामान्य दर्शक उस चलचित्र के भाव को जानने को उत्सुक हो जाते हैं और उनके कदम चलचित्र गृह की ओर बढ़ने लगते हैं । व्यक्ति का अपने निजी विचारों के अनुसार जिज्ञासु होना भी एक गुण है जो अनवरत कल्पनाओं के सृजन डूबा रहता है। कभी-कभी वह ऐसी स्थिति में मग्न हो जाता है कि चिंतनशीलता के चैतन्य में भाव-विभोर हो जाता है। वर्तमान समय में जो प्रतिबद्ध जिज्ञासु हैं, वही भविष्य में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकेंगे या वैज्ञानिक की श्रेणी धारण कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति जो जिज्ञासा से मुक्त हैं, वे अपनी दैनंदिनी में एकदम शांत और सरल हैं। ऐसे कई लोग यथास्थितिवाद के राही होते हैं। जो न कुछ सीख सकते हैं और न किसी को कुछ सिखा सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में यह आमतौर पर देखा गया है कि वर्ग में पढ़ा रहे शिक्षकगण से कुछ ही विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं जो उनकी जिज्ञासा भाव का प्रमाण है, जबकि अधिकतर विद्यार्थी शांत रहते हैं । सहज

लिखने की कला लुप्त हो रही है

विजय गर्ग

'लिखने की खोई हुई कला' डिजिटल संचार के पक्ष में लिखावट की क्रमिक गिरावट को संदर्भित करती है, क्योंकि कीबोर्ड, फोन और टैबलेट पर टाइपिंग आदर्श बन गई है। जबकि प्रौद्योगिकी ने दक्षता और सुविधा ला दी है, लिखावट की गिरावट इस बात पर सवाल उठाती है कि इस प्रक्रिया में क्या खो सकता है।

हस्तलेखन एक कला क्यों है?

1. व्यक्तिगत अभिव्यक्ति: लिखावट अत्यंत व्यक्तिगत होती है। किसी की स्क्रिप्ट की शैली, प्रवाह और विशिष्टता व्यक्तित्व, मनोदशा और वैयक्तिकता को दर्शाती है। इसके विपरीत, टाइप किया गया पाठ एक समान और अवैयक्तिक होता है।

2. सांस्कृतिक महत्व: ऐतिहासिक रूप से, हस्तलेखन कलात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम रहा है, विशेषकर सुलेख और पत्र लेखन में। खूबसूरती से लिखी गई पांडुलिपियों और पत्रों को एक समय संचार और कलात्मकता के मिश्रण के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जाता था।

3. भावनात्मक संबंध: हस्तलिखित नोट्स, पत्र और पत्रिकाएं गर्मजोशी और प्रामाणिकता रखती हैं, जिसका डिजिटल पाठ में अक्सर अभाव होता है। एक हस्तलिखित संदेश प्रयास और इरादे को व्यक्त करता है, जिससे प्राप्तकर्ता के लिए यह अधिक सार्थक हो जाता है।

4. ऐतिहासिक विरासत: कई ऐतिहासिक दस्तावेज़ प्राचीन स्क्रॉल से लेकर व्यक्तिगत पत्रों तक, हस्तलिखित विवरणों के कारण अपनी समृद्धि का श्रेय देते हैं। लिखावट में गिरावट आने वाली पीढ़ियों की समान स्पर्श और दृश्य इतिहास का अनुभव करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।

लिखावट क्यों कम हो रही है?

प्रौद्योगिकी: स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर ने टाइपिंग को तेज़ और अधिक सुविधाजनक बना दिया है।

शिक्षा बदलाव: स्कूल डिजिटल साक्षरता के पक्ष में अक्षर और लेखनी सिखाने पर कम जोर दे रहे हैं।

व्यावहारिकता: टाइपिंग अक्सर अधिक सुपाठ्य, संग्रहीत करने में आसान और संपादन और साझा करने के लिए अधिक सुलभ होती है।

हस्तलेखन को पुनर्जीवित करने का मूल्य

लिखावट की कला को पुनर्जीवित करने का मतलब प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि कलम और कागज के अनूठे लाभों को पहचानना है। हाथ से लिखना:

फोकस और मेमोरी में सुधार: लिखने का स्पर्शनीय अनुभव गहन संज्ञानात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है: डूडल, आरेख और फ्री-फॉर्म नोट्स हाथ से बनाना आसान है।

धैर्य पैदा करता है: लिखावट गति को धीमा कर देती है, जिससे सचेतनता और देखभाल को बढ़ावा मिलता है।

हालाँकि प्रौद्योगिकी हमारे संवाद करने के तरीके को आकार देती रहती है, लेकिन लिखने की कला को जीवित रखना हमारे विचारों, इतिहास और रचनात्मकता के साथ एक ठोस, व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने का एक तरीका है।

रिश्तों का महत्व

विजय गर्ग

घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी । उसकी सास तकरीबन एक साल पहले ही गुज़र चुकी थी । घर में बुज़ुर्ग ससुर और उसके पति के अलावे कोई न था । पति का अपना कारोबार था ।

पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती ।बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती ठीक उसी वक़्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते बहू ,मेरा चश्मा साफ कर मुझें देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता । काम के दबाव और देर होने के कारण क़भी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती लेकिन फ़रिभी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती।

जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया ।पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो ,फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा ।

अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई ।लेकिन फ़रिभी उस दिन वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ़ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा ।

धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फ़रि ऐसा भी वक़्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिलकुल अनसुना करने लगी । ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिलकुल ख़ामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुज़रते वक़्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुज़ुर्ग ससुर भी गुज़र गए।

समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था,वो घूमता रहा घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ़ सफाई का ख़याल आया। वो अपने घर की सफ़ाई में जुट गई। तभी सफ़ाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई ।बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था- ₹दिनांक 26.10.2019.... आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी ज़िंदगी में, घर से निकलते समय, बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं जबकि बुज़ुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए, जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन, अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझें कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना । वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा !! डायरी पढ़कर बहू फूटफूटकर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुके हैं लेकिन फ़रि भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ़ कर, उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में।

जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं।

छोटे शहर से लेकर बड़े सपनों और विशाल यूनिकॉर्न तक: रेज़रपे के 10 साल; 2 युवकों ने बनाई विश्वस्तरीय फिनटेक कंपनी

परिवहन विशेष न्यूज

आज अपनी शुरूआत के एक दशक बाद रेज़रपे विश्वस्तरीय नाम बन चुका है जो लाखों कारोबारों को अपने फाइनैंशियल समाधानों के साथ सशक्त बना रहा है। पिछले दशक के दौरान रेज़रपे तेज़ी से विकसित हुआ और फिनटेक उद्योग में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। आज रेज़रपे 5 मिलियन से अधिक कारोबारों को सशक्त बना चुका है। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई।

नई दिल्ली। आज भारत के फिनटेक स्पेस में अनगिनत ब्राण्ड है जो तेजी से उभर रहे हैं, इस बीच आपको ऐसा भी एक ब्राण्ड मिलेगा जो सही मायनों में इनोवेशन्स और प्रत्यास्थता का दूसरा नाम बन गया है: रेज़रपे। एक दशक पहले जयपुर के दो युवाओं, हर्षिल माथुर और शशांक कुमार ने ऐसी यात्रा की शुरूआत की, जिसने देश के कारोबारों के लिए ऑनलाईन पेमेंट स्वीकार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया।

आज अपनी शुरूआत के एक दशक बाद रेज़रपे विश्वस्तरीय नाम बन चुका है जो लाखों कारोबारों को अपने फाइनैंशियल समाधानों के साथ सशक्त बना रहा है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं सिमटी है: यह दृष्टिकोण, धैर्य और साझा सपनों की साझेदारी पर टिकी है।

यह आइडिया कैसे जन्मा

हर्षिल माथुर और शशांक कुमार दोनों जयपुर में पले-बढ़े। कुछ समय के लिए उनकी पढ़ाई के रास्ते अलग हो गए, हर्षिल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वहीं शशांक ने आईआईटी रूड़की से कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई की। एक छोटे शहर में पले-बढ़े होने के कारण उनमें कड़ी मेहनत, विनम्रता और समाज कल्याण के मूल्य विकसित हो चुके थे।

पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद वे फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, वे जब भी मिलते, कुछ ऐसा करने के लिए बातचीत करते जो वास्तविक समस्याओं को हल कर सके। उन दोनों की इसी सोच ने ऐसा बीज बोया, जो आखिरकार रेज़रपे के रूप में विकसित हो गया।

'शशांक और मेरे-हम दोनों के माता-पिता बैंक में काम करते थे; मेरे पिता ब्रांच मैनेजर थे। आप कह सकते हैं कि उन्हें देखते हुए हम शुरूआत में फाइनैंशियल दुनिया के संपर्क में आ गए थे। लेकिन हमारे परिवार में कोई भी बिज़नेस नहीं करता था।' हर्षिल ने कहा। 2014 में रेज़रपे का आइडिया उभरा, जब भारत में कोई सशक्त ऑनलाईन पेमेंट सिस्टम नहीं था, खासतौर पर स्टार्ट-अप्स और एसएमई के लिए।

'शुरूआत में सोशल क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय पेमेंट लेना मुश्किल होता था। हमने इस समस्या को गहराई से समझने की कोशिश की। सबसे पहली चुनौती थी बैंक से अप्रूवल लेना। मुझे याद है जब मैं जयपुर बैंक गया और कहा ''मैं एक पेमेंट गेटवे शुरू करना चाहता हूं' तब मेरी बात सुनकर सामने वाला कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा था।' शशांक कुमार ने कहा।

बाधाओं को कैसे दूर किया

रेज़रपे का निर्माण इतना आसान नहीं था। हर्षिल और शशांक दोनों ही फिनटेक बैकग्राउण्ड से नहीं थे, यानि उन्हें इस इंडस्ट्री की बारिकियों को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को विकसित करना था। फिर बैंकों का भरोसा जीतना एक और बड़ी मुश्किल थी।

2015 में उनके इस आइडिया ने वाय कॉम्बीनेटर (वायसी) का ध्यान अपनी ओर खींचा, ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टार्ट-अप एक्सेलरेटर्स में से एक हैं। बस फिर क्या था वायसी ने न सिर्फ उनके आइडिया को पसंद किया बल्कि उन्हें शुरूआती फंडिंग और मेंटरशिप भी प्रदान की, जिसकी रेज़रपे को ज़रूरत थी।

'सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वाय कॉम्बीनेटर के साथ इंटरव्यू के बाद हमे लगा कि हम अपना इंप्रैशन बनाने में कुछ खास कामयाब नहीं रहे, और हमने उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन उसी शाम हमें फोन आया- हमें चुन लिया गया था। उस पल ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वाय कॉम्बीनेटर ने हमें एक्सपोज़र दिया और एक विश्वविख्यात ब्राण्ड के साथ जोड़ा। पॉल ग्राहम, जेसिका लिविंगस्टन और सैम ऑल्टमैन से मिलने के बाद हमारी सोच को नई गति मिली और रेज़रपे की यात्रा को नया आयाम मिला।' शशांक कुमार ने कहा।

शुरूआती दिनों में रेज़रपे के लिए प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ जोड़ना मुश्किल था, क्योंकि बहुत से लोग एक अनजान स्टार्ट-अप के साथ काम करने में हिचकते थे। लेकिन हर्षिल और शशांक ने अपने जैसी सोच वाले लोगों को अपने साथ जोड़ा, जो उनके मिशन में भरोसा करते थे।

विकास की यात्रा

पिछले दशक के दौरान रेज़रपे तेज़ी से विकसित हुआ और फिनटेक उद्योग में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। आज रेज़रपे 5 मिलियन से अधिक कारोबारों को सशक्त बना चुका है और पिछले 10 सालों में देश भर में 300 मिलियन से अधिक अंतिम उपभोक्ताओं के साथ जुड़ चुका है।

कंपनी ने 180 बिलियन डॉलर का सालाना टीपीवी (टोटल पेमेंट वॉल्यूम) हासिल कर लिया है और अपने आप को डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग, इनोवेशन एवं विकास में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है। रेज़रपे आज भारत के 100 यूनिकॉर्न्स में से 80 के लिए पेमेंट सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

सिंगल-प्रोडक्ट पेमेंट गेटवे के रूप में शुरूआत करने के बाद आज रेज़रपे मल्टी-प्रोडक्ट कंपनी के रूप में विकसित हो चुका है और भारत के विश्वस्तरीय फिनटेक स्पेस में पेमेंट के कलेक्शन और मुवमेन्ट से जुड़े हर पहलू को आसान बना रहा है।

भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। तकरीबन 250 मिलियन लोग डिजिटल लेनदेन करते हैं। इनमें से तकरीबन सभी ने कभी न कभी रेज़रपे का अनुभव प्राप्त किया है। रेज़रपे की सफलता हर्षिल और शशांक के बीच की साझेदारी का परिणाम है। हर्षिल का दृष्टिकोण और शशांक की टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता- इन दोनों ने मिलकर ऐसे लीडरशिप मॉडल का निर्माण किया है जो उनकी पूरी टीम को प्रेरित करता है।

छोटे शहर के मूल्यों की भूमिका

हर्षिल और शशांक खासतौर पर अपने निवेशकों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने उस समय पर भरोसा किया, जब यह सिर्फ एक आइडिया था। उनके परिवार उनकी ताकत का आधार रहे हैं, जिन्होंने हर समय उनका साथ दिया। उनका मानना है कि रेज़रपे की सफलता उन दोनों की जीत है, इस जीत में उन सभी लोगों का हाथ है जिन्होंने उन पर भरोसा किया, उन्हें सहयोग दिया और हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे।

रेज़रपे और भारत के लिए दृष्टिकोण

रेज़रपे अपनी 10वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। वे दुनिया भर में विस्तार करना चाहते हैं और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए अपने आधुनिक समाधान को इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। रेज़रपे की कहानी दो संस्थापकों की कहानी है जिन्होंने एक साथ मिलकर सफल कंपनी का निर्माण किया; यह उन बड़े सपनों और उन्हें साहस के साथ साकार करनेकी प्रेरक कहानी भी है।

वैरिएंस वाले पोर्टफोलियो: लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सुरक्षित माध्यम

नई दिल्ली। पिछले साल एक मजबूत बुल रन के बाद, इक्विटी बाजार करेक्शन मोड में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें एफआईआई आक्रामक रूप से बिकवाली कर रहे हैं। बढ़ती अस्थिरता ने निवेश रिटर्न को प्रभावित किया है। ऐसे में एक लो-वैरिएंस वाला पोर्टफोलियो, जहां रिटर्न अपेक्षित औसत से बहुत अधिक अलग नहीं होता है, लॉन्गटर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

जबकि औसत रिटर्न, जैसे कि 10 वर्षों में 12 प्रतिशत, आकर्षक हैं, किसी की वास्तविक वित्तीय यात्रा में अक्सर महत्वपूर्ण डेविएशन शामिल होते हैं। यह वैरिएंस पोर्टफोलियो अस्थिरता को उजागर करती है, यह विशेष रूप से वर्तमान समय में झलकता है - कोविड के बाद के दौर में - जोखिम लेने और निवेशकों के उत्साह के कारण निवेश रूझानों में बदलाव आया है।

अस्थिरता को बढ़ाने वाले जोखिम कारक

1. निवेशक व्यवहार: निवेशक, जो पहले डेट और गोल्ड के साथ इक्विटी को संतुलित करते थे, अब इक्विटी, विशेष रूप से मिड और स्मॉल कैप को प्राथमिकता देते हैं, जिससे जोखिम-रिवॉर्ड में अंतर होता है। मिड, स्मॉल और सेक्टोरल फंड्स जैसी जोखिम भरी कैटेगरीज में निवेश सीवाईटीडी 2024 (30 सितंबर तक) में 1.61 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया।

2. मूल्यांकन और ग्रोथ: मार्केट कैप-टू-जीडीपी 147 प्रतिशत (ऐतिहासिक औसत: 94 प्रतिशत) पर है, जो महंगे मूल्यांकन का संकेत देता है। बीएसई 500 कंपनियों के लिए राजस्व और आय वृद्धि पिछली तिमाहियों में तेजी से घटी है।

3. जियोपॉलिटिकल तनाव: लगातार यूएस-चीन ट्रेड वॉर और अन्य वैश्विक मुद्दे जोखिम को बढ़ाते हैं।

लो-वैरिएंस वाले पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का लाभ

लार्ज-कैप कंपनियों को आमतौर पर स्थिर आय और तरलता के कारण कम अस्थिरता का अनुभव होता है। अक्टूबर 2024 तक, निफ्टी 100 टीआरआई वैल्यूएशन (पी/ई: 23.1, पी/बी: 3.66) निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई (पी/ई: 43, पी/बी: 5.44) और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई (पी/ई: 32.4, पी/बी: 4.25) से कम है।

लो-वैरिएंस रणनीतियों में सक्रिय प्रबंधन को जोड़ने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। ब्याज दरें, यूएसडी डायनेमिक्स और तेल की कीमतें जैसे कारक, मैक्रो संकेतकों के साथ, पैसिव नियम-आधारित तरीकों से परे अवसरों की पहचान करने में मदद करते हैं। निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 टीआरआई ने 2005 से सीवाईटीडी 2024 तक 60 प्रतिशत वर्षों में निफ्टी 100 टीआरआई से बेहतर प्रदर्शन किया है।

सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, क्या खरीदारी का बन गया मौका?

परिवहन विशेष न्यूज

सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट आई। इसकी वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कमेंट है। उन्होंने कहा कि फेड अब 2025 के अंत तक ब्याज दरों में दो बार कटौती का अनुमान लगाता है। सितंबर में उसने चार बार दर कटौती का अनुमान लगाया था। इससे सोने में निवेश और खरीदारी का माहौल एकदम से सुस्त हो गया है।

नई दिल्ली। सोने की कीमतों गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं, चांदी भी 200 रुपये सस्ती हो गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोने को लेकर कारोबारियों का रुख ग्लोबल लेवल पर काफी कमजोर रहा। जौहरियों ने भी सोने की खरीद में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।

इसके चलते 24 कैरेट वाले सोने का दाम 800 रुपये गिरकर 78,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 79,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गुरुवार को चांदी भी 2,000 रुपये गिरकर 90,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई। एक दिन पहले यह 92,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

सोने और चांदी के दाम में क्यों आई गिरावट

व्यापारियों का कहना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की। यह सोने के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के आक्रामक रुख अपनाने से सर्राफा की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि फेड अब 2025 के अंत तक ब्याज दरों में दो बार कटौती का अनुमान लगाता है। सितंबर में उसने चार बार दर कटौती का अनुमान लगाया था।

एक्सपर्ट की क्या है राय

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, "फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के बाद सोने में भारी गिरावट आई, क्योंकि फेड ने अगले साल के लिए ब्याज दरों में कटौती को पहले के अनुमान से कम बताया है।" अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 2.47 प्रतिशत गिरकर 29.98 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

एबन्स होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा, "निवेशक गुरुवार देर रात जारी होने वाले अमेरिकी साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इससे श्रम बाजार की मजबूती का आकलन करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक के आंकड़े आएंगे। उनकी भी अहमियत काफी ज्यादा रहेगी।"

क्या सोने की कीमतों में जारी रहेगी गिरावट

पिछले स्तरों की तुलना में बुलियन मार्केट में गिरावट जरूर आई है, लेकिन निवेशक धीरे-धीरे अपना निवेश बढ़ाएंगे। इससे कीमतें मजबूत हो सकती हैं। एबन्स होल्डिंग्स के मेहता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, लेकिन ब्याज दरों में अतिरिक्त कटौती में किसी भी तरह की देरी से नियर टर्म में सोना सस्ता हो सकता है। यह गोल्ड में निवेश का अच्छा मौका भी होगा।

मिलवुड केन इंटरनेशनल के फाउंडर और सीईओ निश भट्ट ने कहा, 'हमें लगता है कि अस्थिरता जारी रहेगी, मुख्य संकेत अमेरिका में नए प्रशासन और व्यापार शुल्कों की घोषणा से होंगे।' उन्होंने कहा कि व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजारों में भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सोने की कीमतें मजबूत रहेंगी। हालांकि, रुपये में कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी।

आईटीआर में यह जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी, लग जाएगा 10 लाख का जुर्माना; जानें बचने का तरीका

परिवहन विशेष न्यूज

ITR revision deadline अगर आपके पास विदेश में कोई प्रॉपर्टी है या किसी भी स्रोत से कमाई हो रही है तो उसकी जानकारी आईटीआर में देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी देकर आईटीआर में संशोधन करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक की मोहलत दी है।

नई दिल्ली। भारत में हमेशा से काला धन (Black Money) और अघोषित आय बड़ा मुद्दा रहा है। टैक्स अधिकारी अक्सर उन लोगों को नोटिस भेजते हैं, जो विदेश में निवेश तो करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में उसका खुलासा नहीं करते। इससे देश की इकोनॉमी तगड़ी चोट पहुंचती है, क्योंकि काले धन से भ्रष्टाचार और महंगाई तो बढ़ती ही है, सरकारी खजाने को भी भारी चपत लगती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 दिसंबर, 2024 को एक ब्रोशर जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि किन करदाताओं को 31 दिसंबर, 2024 तक अपने आईटीआर में शेड्यूल्ड फॉरेन असेट (एफए) और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आप भी आईटीआर में अपने विदेशी निवेश का खुलासा नहीं करते, तो उसे काला धन माना जा सकता है। इसके लिए 10 लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आईटीआर में विदेशी आय की जानकारी देना जरूरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को अपने विदेशी खाते की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद रखें या प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। कम शब्दों में कहें, तो आपको विदेश में स्थिति हर संपत्ति के बारे में बताना होगा, फिर चाहे उससे आपको कोई कमाई हो रही हो या नहीं।

विदेशी संपत्ति और कमाई की जानकारी न देने पर क्या होगा?

पिछले कुछ साल में भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ कई समझौते किए हैं। इससे अगर कोई नागरिक विदेश में निवेश कर रहा है, तो उसकी जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसे में विदेशी निवेश की जानकारी न देने वाले शख्स पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विदेशी संपत्ति और कमाई का खुलासा किसे करना होता है?

यह नियम उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनकी विदेश में कोई संपत्ति है या वहां से उन्हें कमाई हो रही है। विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, इक्विटी, व्यावसायिक निवेश और प्रॉपर्टी होल्डिंग्स जैसी चीजें शामिल हैं। विदेशी स्रोतों से कमाई में ब्याज आय, लाभांश और सकल आय शामिल हैं।

आईटीआर में विदेशी संपत्ति की जानकारी कैसे दें?

आप अपनी विदेशी संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। जैसे कि आपके पास कैसी संपत्ति है, आपने उसे कब खरीदा, उससे आपको कितनी कमाई हुई। आपने संपत्ति खरीदने या कमाई पर विदेश में जो टैक्स दिया है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। आप पूरी को कंपाइल करके आईटीआर में आसानी से भर सकते हैं। अग आप दोहरे कर बचाव समझौते के तहत पात्र हैं, तो टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए अनुसूची टीआर के साथ फॉर्म 67 जमा करें।

₹25 लाख तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार की स्कीम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को अपने पहले कार्यकाल में ही लॉन्च किया था लेकिन इसके दूसरे चरण को मंजूरी अगस्त 2024 में दी गई है। इस योजना में शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सरकार मदद कर उनके घर के सपने को साकार करती है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी।

क्या है पात्रता

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही यह जरूरी है कि लाभार्थी के पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं हो। ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।

क्या होता है ईडब्ल्यूएस

जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में कैटेगरी में रखा गया है।

चार तरह से लागू

पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के अलावा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत किया जाता है।

क्या है बीएलसी और एएचपी

बीएलसी के जरिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नए आवास बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। एएचपी के तहत किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एआरएच में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रित/छात्रों और अन्य समान हितधारकों के लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवासों का निर्माण किया जाएगा।

क्या है ब्याज सब्सिडी योजना

ब्याज सब्सिडी योजना की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को खास तरह की सुविधा मिलती है। ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। बता दें कि लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक घटक का चुनाव कर सकते हैं।

प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन !

आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व धीरे-धीरे एक बार पुनः रसायन मुक्त प्राकृतिक और परंपरागत खेती की ओर बढ़ रहा है। भारत सदियों सदियों से विश्व का एक बड़ा कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी है और यहां प्राकृतिक खेती होती रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि हरित क्रांति से पहले भारत परंपरागत और प्राकृतिक खेती करता रहा है। हरित क्रांति के दौरान कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग बढ़ा और आज एक बार फिर भारत परंपरागत और प्राकृतिक खेती की ओर क़दम बढ़ा रहा है। वास्तव में प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों जैसे कि देसी गाय का मल-मूत्र, विविधता के माध्यम से कीटों के प्रबंधन के साथ ही खेती से विभिन्न सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्करण(रसायन मुक्त कृषि पद्धति) किए जाने पर आधारित एक साधारण कृषि पद्धति है। कहना ग़लत नहीं होगा कि हाल ही में जो मिशन भारत में शुरू किया गया है इस मिशन का मुख्य मकसद किसानों को रासायनिक खेती से दूर करके प्राकृतिक खेती(स्थानीय पशुधन, प्राकृतिक तरीके और विविध फसल प्रणालियों का इस्तेमाल) की ओर ले जाना है। इसी क्रम में भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिये एक अलग तथा स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) शुरू किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में 25 नवंबर 2024 को ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि इस योजना का 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा- 1584 करोड़ रुपये; तथा राज्य का हिस्सा- 897 करोड़ रुपये है। वास्तव में एनएमएनएफ पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पाठकों को जानकारी के लिए बताता चलूं कि अगले दो वर्षों में एनएमएनएफ को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15 हजार समूहों में लागू किया जाएगा तथा 01 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती (एनएफ) शुरू की जाएगी। वास्तव में, इसके लिए 10,000 जैव-आदान संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए जाएंगे और 2000 मॉडल प्रदर्शन फार्म बनाए जाएंगे। किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार पहुंच प्रदान की जाएगी। वास्तव में एनएमएनएफ का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह मिशन किसानों की खेती की लागत को कम करेगा वहीं दूसरी ओर बाहरी खरीदारी पर निर्भरता कम करने में भी किसानों की मदद करेगा। कहना ग़लत नहीं होगा कि प्राकृतिक खेती से एक ओर जहां मिट्टी की सेहत में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर इससे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। कहना ग़लत नहीं होगा कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा और जल उपयोग दक्षता में सुधार के माध्यम से, मिट्टी के सूक्ष्मजीवों और एनएफ में जैव विविधता में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा इकोसिस्टम का निर्माण और रख-रखाव करेगी। विविध फसल प्रणालियों को भी इससे बढ़ावा मिल सकेगा। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सेहत(उर्वरता बढ़ेगी) अच्छी होगी तथा जलभराव, बाढ़, सूखे आदि जैसे जलवायु जोखिमों से संभलने का सामर्थ्य पैदा करने में मदद मिल सकेगी। प्राकृतिक खेती के कारण स्वास्थ्य के जोख़िम भी निश्चित ही कम होंगे और साथ ही इससे आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ धरती उपलब्ध हो सकेगी। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि प्रकृति और पर्यावरण को निश्चित ही इससे फायदा होगा। गौरतलब है कि जलवायु के अनुकूल खेती से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन(एनएमएनएफ) के तहत, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे और इन्हें अनुभवी और प्रशिक्षित किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इस मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएंगे। जैविक संसाधन केंद्र भी स्थापित होंगे। इतना ही नहीं, मिशन के तहत 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक किसान अपने पशुओं का उपयोग करके या बीआरसी से खरीद कर जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे कृषि संबंधी संसाधन तैयार करेंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसानों की मदद करने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए 30,000 कृषि सखियों/सीआरपी को तैनात किया जाएगा। अंत में यही कहूंगा कि आज के इस आधुनिक युग में किसान एक बार फिर परंपरागत प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं, जैसा कि आज हमारी ज्यादातर जमीनें रासायनिक खादों, उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पहले ही जहरीली हो चुकीं हैं। सरकार ने अब प्राकृतिक खेती की महत्ता को समझते हुए देश में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) शुरू कर दिया है। इससे निश्चित ही किसानों और पर्यावरण को अभूतपूर्व लाभ पहुंचेंगे। प्राकृतिक खेती से भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी। इतना ही नहीं इससे मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा।फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होगी। निश्चित ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से हर तरफ लाभ ही लाभ होंगे।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार,

गौतमबुद्ध नगर में होगा प्रदेश का पहला गौ कुंभ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे गौभक्तों को आशीर्वाद

परिवहन विशेष न्यूज

गौतमबुद्ध नगर में 1 और 2 मार्च 2025 को प्रदेश का पहला गौ कुंभ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन गौ संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में गौभक्तों को आशीर्वाद देंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा:

विहंगम योग संत समाज के राष्ट्रीय संत नरेश अग्रवाल ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। बैठक में कैलाश चंद किला ने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस महोत्सव में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल होंगे।

उद्देश्य और सहभागिता:

इस गौ कुंभ का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। देशभर से गौ प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता इस आयोजन में भाग लेकर गौ संरक्षण के महत्व को रेखांकित करेंगे। कार्यक्रम में गौ पालन के विविध पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें गौ संरक्षण की रणनीतियां, गौ उत्पादों के उपयोग और समाज में गोवंश के महत्व को विस्तार से समझाया जाएगा।

विशेष योगदान:

बैठक में रेनू, श्रेया, भारत रत्न जुगल किशोर और निशु गुप्ता जैसे कई गणमान्य व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पहला गौ कुंभ न केवल गौ संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि समाज में गोवंश के प्रति संवेदनशीलता भी जगाएगा।

यह आयोजन गौ संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और गोवंश के महत्व को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग्रामीणों को भुगतान किए बगैर ही जालसाजी से हड़पी 7 करोड़ की जमीन, सीएम यूपी से कार्यवाही की मांग

- 4 करोड़ की फर्जी चेक देकर हथियाई 7 करोड़ से अधिक कीमत वाली जमीन, दाखिल खारिज भी करा दो कीमती भूखंड भी डाले बेंच,
- मामले में हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने खोला पीड़ित गांव वालों के पक्ष में मोर्चा , एफ आई आर की मांग

सुनील बाजपेई

कानपुर। धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से करोड़ों की कीमत वाली जमीनों को हड़पने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह भी कि ऐसे अधिकांश मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अहम भूमिका होती है। ऐसे मामले में वह शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति का साथ देने के बजाय पैसे और ऊंची पहुंच से संपन्न उन दबंगों का साथ देते हैं ,जो धोखाधड़ी और जालसाजी से करोड़ों की जमीन हड़पने में सफल रहते हैं। इस तरह के अधिकांश मामलों में वास्तविक भूमि मालिक पीड़ित व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर लगाता ही रह जाता है और इसी बीच गैर कानूनी तरीके और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने वाले लोग उसे बेचकर करोड़ों के बारे में भी करने में सफल हो जाते हैं।

चर्चा का विषय बना जमीन के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी का एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आने के बाद हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने पीड़ित ग्रामीणों के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर आंदोलन की भी धमकी दी है।

हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने योगी सरकार के नाक के नीचे इन्दिरानगर, लखनऊ में दबंग द्वारा फर्जी व जाली चेको के माध्यम से 7 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में लिखाते हुए रजिस्ट्री करा कर उसे बेचने और दाखिल खारिज कराने के प्रयास की घोर निन्दा और एफ आई आर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए बताया कि अवघराम, संतोष, अरुण चौहान एवं अरविन्द पुत्रगण स्व० रामचरन, निवासी निजामुद्दीनपुर, फरीदीनगर, सीमैप, लखनऊ ने पूर्वजों की जमीन भूमि खाता सं- 00056, खसरा सं 84, कुल रक्बा 0.9540 हे० में से रक्बा 0.80725 हे० यानि 8072.5 वर्गमीटर, स्थित निजामुद्दीनपुर, इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड, लखनऊ चार करोड़ रुपये में पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करके (क्रेता) प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री दल बहादुर सिंह, निवासी-221 क/1, ग्राम व पोस्ट- थौरी, मुसाफिरखाना, जिला अमेठी को विक्रय किया था, जिसे 30.10.2024 को उप-निबन्धक, सदर तृतीय, लखनऊ द्वारा रजिस्ट्रीकृत भी कर दिया गया है।

गरीब मजदूरों के हित में न्याय के लिए सफल संघर्ष में लगातार लगे रहने वाले हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि इन बेचने वालों को उक्त भुगतान प्रदीप कुमार सिंह द्वारा पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से चार-चार के क्रम में अलग अलग दिनांक में दिए गए थे, जिन्हें इन मजदूरों ने जब अपने बैंक खाते में भुनाए जाने हेतु प्रस्तुत किये गए तो उक्त समस्त चेक अनाद्रित (बाउन्स) हो गए।

पीड़ित पक्ष के साथ हुई जमीन हड़पने की इस करोड़ की धोखाधड़ी के खिलाफ उन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत वरिष्ठ मजदूर नेता राकेश मणि पांडे ने बताया कि रजिस्ट्री प्राप्त करने के पश्चात श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा उक्त भूमि में से दो भूखण्ड दो अन्य लोगो को गैर कानूनी तरीके से बेचा भी जा चुका है।

हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि बिना भुगतान दिए प्रदीप कुमार सिंह द्वारा उक्त रजिस्ट्रीकृत भूमि को दिनांक 13.11. 2024 को तहसीलदार सदर के कार्यालय में भूमि को दाखिल खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। जिसके खिलाफ उसे निरस्त किये जाने हेतु ग्रामीणों द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।

कई श्रमिक आंदोलनों के भी सफल अगुवाकार रहे हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से जो चेक ग्रामीणों को दिया है वो किसी मेसर्स डी बी एस धर्मकांटा फर्म के द्वारा जारी की गयी है, यह कृत्य भी प्रदीप कुमार सिंह द्वारा पूर्वनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है।

फिलहाल चर्चा का विषय बने जमीन से संबंधित करोड़ की धोखाधड़ी वाले इस मामले में वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय की अगुवाई में पीड़ित गांव वालों की ओर से चेक की प्रतियों और बैंक द्वारा द्वारा चेक वापस करने सम्बन्धी जारी मेमो की प्रतियों संलग्न करते हुए जिलाधिकारी, तहसीलदार सदर थानाध्यक्ष इन्दिरानगर और शासन के समस्त अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित करने के साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराकर न्याय की मांग की गई है। वहीं श्रमिक नेता राकेशमणि पाण्डेय ने गरीब मजदूरों को संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें न्याय दिलाने हेतु संबंधित मामले में दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही नहीं किए जाने पर हिन्द मजदूर किसान पंचायत द्वारा आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है।

संगम विश्वविद्यालय द्वारा जुगाड़ मेला (2.0) का आयोजन

।।प्रविष्टि की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025।।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा ,हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी संगम विश्वविद्यालय जुगाड़ मेला " नवाचार -भारतीय तरीक़ा" का आयोजन करने जा रहा है ।यह मेला विज्ञान के क्षेत्र में बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान भारती एवं संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता (जुगाड़ मेला वेस्ट टू टेस्ट) का आयोजन आगामी 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को प्रारंभ किया जाएगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफ़ेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु जुगाड़ मेला का आयोजन कर रहा है इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मार्केटिंग हेड डॉ.अमित जैन ने बताया कि इस जुगाड़ मेला में कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय निजी एवं आईटीआई संस्थानों के विद्यार्थी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे ।संस्था की तरफ़ से अधिकतम दो टीमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य होगी और प्रत्येक टीम एक विद्यार्थी एक ही प्रोजेक्ट में भाग ले सकेगा । रजिस्ट्रार प्रोफ़ेसर राजीव मेहता ने बताया कि जुगाड़ मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है ।विश्वविद्यालय उप कुलपति प्रोफ़ेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने बताया कि राजकीय ,निजी विद्यालय, आईटीआई संस्थान इस जुगाड़ मेला में प्रतिभागी के रूप में जुड़ने हेतु रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी 2025 तक करवा सकते हैं उसके पश्चात आए हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जन-सुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर करें शत-प्रतिशत निराकरण – अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। प्रत्येक तीसरे गुरुवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई में गुरुवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये। ज़िला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर सुनील पुनिया ने जन-सुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश जारी किए।

एडीएम पुनिया ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जन-सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचाना है। अतः सभी अधिकारी जन-सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जनसुनवाई में कुल 18 प्रतिवाद प्राप्त हुए जिसमें से 5 परिवादों का मौक़े पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से अतिक्रमण, रास्ते के प्रकरण, पानी भराव की समस्या, गंदगी, जल निकासी, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने, तथा पुलिस संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए जिनको एडीएम पुनिया ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर त्वरित तथा संतुष्टि पूर्ण समाधान के लिए निर्देशित किया।

ज़िला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

जिला जनअभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमे 22 प्रकरणों पर सुनवाई की गई तथा मौक़े पर 9 का निस्तारण किया गया। बैठक में लम्बित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश देते हुए एडीएम पुनिया ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले सभी प्रकरणों को निश्चित समयावधि में निस्तारित किया जाये। एडीएम पुनिया ने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 6 महीने से अधिक लम्बित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिये संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत दी जाये। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राजेश आर्य , सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा सभी उपखंड से उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

धनबाद में बालू माफियाओं ने अधिकारियों को पीटा, मामला दर्ज़

सिंहभूम में बालू के कारण हत्या के बाद स्थिति गंभीर, डीसी-एस पी का रात में कैंप

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

चाईबासा, आये दिनों झारखंड में बालू माफियाओं का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कहीं तस्करी निर्विरोध जारी है तो कहीं पर अधिकारी पिटाई हो रही हैं । आज ऐसी ही एक घटना धन्यवाद के सरायढेला में बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला किया है। तस्कर बालू लदे दो ट्रैक्टर को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हमले के दौरान खनन इंस्पेक्टर पर पत्थर से हमला किया गया। तीन इंस्पेक्टर के मोबाइल को तोड़ दिया गया। खनन विभाग के गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। अधिकारियों के मोबाइल , लैपटाप तक तोडे गये । इससे पहले भी

गोविंदपुर सीओ पर बालू माफिया ने इसी तरह का हमला किया था और उनके गाड़ी और मोबाइल को तोड़ा गया था।

इससे पहले भी अवैध बालू माफियाओं का दुस्साहस देखने को मिला था। पिछले महीने ही गोविंदपुर अंचल अधिकारी पर हमला हुआ था। इन घटनाओं ने धनबाद में बालू माफियाओं के बढ़ते मनोबल और स्थानीय प्रशासन की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। अब नया मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

उधर पश्चिमी सिंहभूम में में बालू कारोबार चरम पर है । झारखंड में बालू घाटों का टेंडर नहीं हुआ है जहां माफियाओं का पौ बारह है । बालू के कारण गत दिनों माओवादियों ने दो लोगों की हत्या की थी , जिसके बाद दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश वर्जित कर छह सात लोगों की हत्या कर चुके हैं । जो बेहद संवेदनशील प्रसंग है । स्थिति बिगड़ता देख उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम ने देर रात वहां कैंप भी कर चुके हैं। बहरहाल

हुई हत्या से उपजे स्थिति असामान्य बनी हुई है । उधर गुदड़ी , आनंदपुर, इधर आयता, कुर्सी , तांतनगर में धड़ल्ले से बालु चोरी जारी है । जब शहर में बाहर हजार रूपये का बालू पांच हजार में विक रहा है ।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ.प्र. ने उठाया आन्दोलन का बिगुल

आगरा, संजय साग़र सिंह। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी ने प्रदेश भर के फार्मेसिस्टों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन का उद्देश्य शासन और महानिदेशक के अपेक्षात्मक रवैये को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाना है।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री एवं जिलामंत्री, डी.पी.ए. आगरा डॉ. रविन्द्र सिंह राना ने बताया कि इस आंदोलन की शुरुआत 20 दिसम्बर 2024 को आगरा में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरने से होगी। इस धरने में जिले के सभी फार्मेसिस्ट भाग लेंगे और वे माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे। इसके बाद, 22 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक फार्मेसिस्टों द्वारा सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 3 जनवरी 2025 को आगरा मंडल मुख्यालय पर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय पर भी धरना आयोजित किया जाएगा। श्री रविंद्र सिंह राणा ने आगे बताया कि आंदोलन के अंतिम चरण में, 31 जनवरी 2025 को प्रदेशभर के फार्मेसिस्ट लखनऊ स्थित महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां अग्रिम आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। इस संबंध में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन आगरा शाखा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया है कि सभी फार्मेसिस्टों को धरने में भाग लेने की अनुमति दी जाए और ज्ञापन स्वीकार किया जाए। अंत में उन्होंने कहा, "यह आंदोलन फार्मेसिस्टों के अधिकारों की रक्षा और उनकी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए चलाया जा रहा है।"

राजनैतिक द्वंद में संसद की गरिमा क्यों खण्डित कर रहे

स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

'कोई भी सत्र हो लोकसभा व राज्यसभा नहीं चल पा रही है। घमासान ना जाने क्या दिखायेगा। संसद से सड़क तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत ग़लत है।

संसद परिसर में यह क्या हो रहा है क्या भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का यह सही परिदृश्य है ? हंगामा चिल्ला-चिल्ला कर संसद की कार्यवाही पर बधा डालना क्या सही है। आरोप-प्रत्यारोप के यह रंग अपनी अभिव्यक्ति को जिम्मेदारी भरें तरीके से होनी चाहिए। अपनी बातों में विरोध प्रदर्शन करें दमदारी से पटल पर बात रखें । चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों को इस संविधान की बात को लोकतांत्रिक मंदिर में अपनी सजगता से रखना चाहिए। इस तरह सड़क छाप नाकारात्मक राजनीति को क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे देश के राजनेता ? बीच संसद परिसर में धरना प्रदर्शन विरोध क्या सत्ता पक्ष को भी शोभा नहीं देता। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं का जोर अजमाइश धक्का-मुक्की मार्यदा अनुरूप नहीं है। जिन महान नेताओं के प्रतिफल से लोकतंत्र गोरवान्वित है उनके मान सम्मान को खण्डित करने की राजनीति या पब्लिसिटी स्टंट राजनीति के लिए घातक सिद्ध ना हों जाये। सियासत के लिए इस तरह के अचारण में लगे पक्ष विपक्ष का संयम आखिर क्यों खत्म हो रहा है। महात्मा गांधी जी हो या बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या अटल बिहारी वाजपेई जी सभी ने देश के लिए एकजुटता के साथ काम किया पर वर्तमान राजनीति में भाजपा व कांग्रेस या अन्य दलों में इतनी खाई क्यों पैदा हो गई इस का चिंतन बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य राजनेता बहुत ही वरिष्ठ राजनेता व अनुभवी राजनीतिक होते हैं वहां इस तरह की धक्का पॉलिटिक्स का यह कोई काम नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति भारत को किधर ले जा रही है ? इस बात की चिंता क्यों नहीं हो रही है। आप सभी की इस गुत्थम-गुत्था में देश की जनता में क्या संदेश जा रहा है। करोड़ों स्पये की बारबदी हो रही है संसद की चलने नहीं दी जाती है इस का समाधान कब होगा कोई नहीं बताता है। संसद परिसर में इस तरह के हल्लाबोल की जरूरत नहीं होना चाहिए यह कोई राजनिति का अखाड़ा नहीं है इस बात का ख्याल रखना सम्मनिय सांसदो का कार्यत्वय होगा।

यह कैसी विडम्बना है यह कैसी संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। हद हो गई है आंबेडकर जी पर ग्रहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर जो घटनाक्रम हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा पीढ़ी इस तरह के व्यवहार से क्या प्रेरणा लेंगी। जनप्रतिनिधि देश के भाग्य विधाता होते हैं जो अपने राष्ट्र की अच्छाई के लिए सकारात्मक सोच से ओतप्रोत रहते हैं पर वर्तमान में राजनीति अपनी अपनी पार्टी तक ही सिमट गई है।

जो ग़लत है देश की सभी राजनैतिक दलों को पार्टीयों को सबसे पहले राष्ट्र के प्रति उसके बाद जनमानस के लिए अपनी बात रखना चाहिए।

नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ ठेकेदारों और वेंडर्स का प्रदर्शन: 600 करोड़ रुपये का बकाया

नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ ठेकेदारों और वेंडर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। श्री श्याम वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को सेक्टर 118 स्थित रोमानो प्रोजेक्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों और वेंडर्स के साथ किए जा रहे अन्याय और धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाना था। इस दौरान एनसीएलएटी कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट ऑफिसर हितेश गोयल के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही उनका पुतला फूंका गया।

बकाया राशि और भुगतान में देरी:

श्री श्याम वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भाटी ने बताया कि सुपरटेक के करीब 18 प्रोजेक्ट में 250 से ज्यादा वेंडर्स का 600 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। पिछले 3 साल से किसी भी वेंडर को भुगतान नहीं किया गया है। वेंडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि आईआरपी हितेश गोयल ने उन्हें आश्वासन देकर काम भी करवाया, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं किया गया। अब संगठन के पदाधिकारी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रदर्शन में शामिल प्रमुख व्यक्ति:

प्रदर्शन में श्री श्याम वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भाटी, उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, सचिव अनुभव चौधरी, संयुक्त सचिव कुलदीप अरोड़ा, कोषाध्यक्ष अंकुर जैन, कार्यकारी सदस्य सचिन सोनी, आकाश गर्ग, दीन मोहम्मद, रणबीर यादव और अन्य 100 से अधिक लोग शामिल थे।

आगे की कार्रवाई:

वेंडर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो वे आगामी दिनों में और भी बड़े प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने न्याय की उम्मीद जताई है और अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील की है।

यह स्थिति सुपरटेक बिल्डर और संबंधित अधिकारियों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, और देखना होगा कि वे इस मुद्दे का समाधान कैसे करते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023